RNI NO. PUNBIL/2014/59416

UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

गुस्ताखी माफ

नकद नरायण की बड़ी, महिमा अपरंपार।
जिसने बांटा खोल दिल, उसका बेड़ा पार।
उसका बेड़ा पार, किनारे लगती नैया।
दोनों हाथों अरे, बांटना पड़े रुपैया।
कह साहिल कविराय, जरा-सा भी ना डरिए।
पहले बांटें कैश, ऐश फिर जमकर करिए।

प्रस्तुति : डॉ. राजेन्द्र साहिल

VOL: 03 | ISSUE 183 | SUNDAY DATE 26-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

8th EDITION

LRGMA®

United we are...Stronger we are...

FOMERAH GREENS
RESORT STYLE LIVING
1 min. from South City
Bypass at Hambran Road

CBR
SAARK KNITS

INDIA'S LARGEST GARMENT EXHIBITION

Date :
26 27 28
JULY, 2026

Venue:
PUNJAB AGRICULTURE UNIVERSITY
FEROZEPUR ROAD, LUDHIANA.

FASHION LIFESTYLE INNOVATION

AUTUMN / WINTER Trends

ORGANISED BY:
LUDHIANA READYMADE GARMENTS MANUFACTURERS ASSOCIATION

रात जागो - देश जागो ' के तहत छात्रों पर हुए पुलिस दमनकारी लाठीचार्ज के विरोध में किया, प्रदर्शन

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 25 जुलाई । दिल्ली जंतर मंतर पर छात्र युवा आंदोलन पर बर्बर लाठी चार्ज के खिलाफ रात जागो-देश जागो कार्यक्रम के तहत जीटी रोड नेशनल हाईवे पानीपत शहर संविधान चौक पर रात्रि 8:00 बजे केंद्र की भाजपा नेतृत्व वाली मोदी सरकार के खिलाफ सैकड़ो की संख्या में छात्र अभिभावक, किसान, मजदूर, कर्मचारी, महिला , प्रगतिशील सामाजिक संगठनों के

सैकड़ो कार्य कर्ता उतरे सड़कों पर, पालिका बाजार के अंदर निकाला विरोध जुलूस। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र की भाजपा नेतृत्व वालीमोदी सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए हम अपने देश के भविष्य अपने बच्चों के खिलाफ किसी भी पुलिस दमन को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम अपने देश के बच्चों के भविष्य के लिए जारी इस देशव्यापी छात्र आंदोलन में पूरी ताकत के साथ संघर्ष में शामिल रहेंगे। सन 2014 से देश भगत मेहनतकश जनता की दुश्मन सरकार ने सबसे पहले हमला देश के किसान और मजदूरों पर बोला उनके खिलाफ काले कानून बनाए गए। ऐतिहासिक किसान जन आंदोलन हुआ तानाशाह मोदी सरकार ने 700 से ज्यादा किसानों की शहादत के बाद काले कानून को वापस लिया गया, मजदूरों के श्रम कानून को खत्म करके चार लेबर कोड बनाए गए।

उन्होंने कहा कि देश का यह छात्र आंदोलन जन आंदोलन बनता जा रहा है। प्रदर्शन के माध्यम से मांग की कि तुरंत देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को बर्खास्त किया जाए , नई शिक्षा नीति रद्द की जाए, नीट व अन्य परीक्षा लेने वाली प्राइवेट कंपनी ठळअ को खत्म किया जाए और परीक्षा सरकारी एजेंसी द्वारा करवाई जाए, एक देश एक परीक्षा नहीं चलेगी, लाठी चार्ज करने वाले पुलिस अधिकारियों दोषियों के खिलाफ कार्रवाई हो, छात्रों के खिलाफ बनाए गए सभी आपराधिक मुकदमे वापस लिए जाए, नीट परीक्षा रद्द होने के कारण आत्महत्या करने वाले परिवारों को एक करोड़ का मुआवजा दिया जाए। सबसे मुख्य बात देश के प्रधानमंत्री मोदी जो इस हालात के लिए पूरी तरह से जिम्मेवार। वर्तमान समय में जनरल डायर की तरह दिल्ली पुलिस को आदेश देने वाले गृहमंत्री अमित शाह कड़े शब्दों में निंदा करते हुए कहा कि तुरंत प्रधानमंत्री और गृहमंत्री नैतिकता के आधार पर अपना पद छोड़ें।

इनैलो पार्टी ने जंतर-मंतर पर छात्रों के साथ हुए अभद्र व्यवहार व लाठीचार्ज के विरोध में महामहिम राष्ट्रपति के नाम पर सौंपा, ज्ञापन

» पानीपत, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

इंडियन नैशनल लोकदल पार्टी जिला पानीपत के सभी पदाधिकारी द्वारा दिल्ली के जंतर-मंतर पर नीट पेपर लीक और अपने हक की आवाज को युवा छात्र शांतिप्रिय तरीके से प्रदर्शन करते हुए संसद मार्च कर रहें थे। उनके प्रदर्शन को रोकने के लिए केन्द्र सरकार ने छात्रों पर बर्बरता पूर्वक लाठी चार्ज किया और हमारी छात्र बच्चियों के साथ भी अभद्र व्यवहार करते हुए लाठियां बरसाई। सरकार का बच्चों के प्रति इस प्रकार का कृत्य सरासर गलत व निंदनीय है।

पत्रकारों से बातचीत करते हुए कपिल काबडी प्रदेश उपाध्यक्ष एस सी प्रकोष्ठ ने कहा कि लोकतंत्र में शांति पूर्वक प्रदर्शन करना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। युवा छात्र हमारे देश का भविष्य है और युवाओं की आवाज को लाठियों व दमनकारी नीतियों के दम पर दबाने की कोशिश को इनेलो पार्टी किसी कीमत पर बर्दाश्त नहीं करेगी। उसके विरोध में आज इनेलो पार्टी के सभी जिला

पदाधिकारियों ने युवा प्रधान अमन मांड़ी के साथ माननीय राष्ट्रपति महोदय के नाम जिला उपायुक्त को ज्ञापन सौंपा और मांग की जल्द से जल्द केन्द्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो।

प्रदर्शन के दौरान छात्रों के साथ उनके समर्थक गिरफ्तार किए गए रिहा किया जाए, और देश की शिक्षा प्रणाली में व्यापक सुधार हो। ताकि भविष्य में कोई भी बच्चा अपने जीवन को लेकर गलत कदम न उठाए।

इस अवसर पर हेमराज जागलान, नवीन भालसी, अमन मांड़ी, राजेन्द्र जागलान, सितम पाल राठी, महाबीर नंबरदार, राजू नांदल, जय भगवान फौजी, नवीन, अंकित मांड़ी, व अन्य युवा साथी मौजूद रहे।

प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कॉलेज, पानीपत में दो दिवसीय हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप ' पलीमन - 26 ' का सफल आयोजन

» पानीपत, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कॉलेज, पानीपत द्वारा 24 एवं 25 जुलाई 2026 को दो दिवसीय हैंड्स-ऑन ट्रेनिंग वर्कशॉप 'प्लेनम 2026 का सफल आयोजन किया गया। कार्यशाला का विषय ' था। फिजियोथेरेपी में टेपिंग तकनीकों और ड्राई नीडलिंग पर व्यापक और गहन ज्ञान के बारे में प्रायोगिक जानकारी ।इस कार्यशाला का उद्देश्य फिजियोथेरेपी के विद्यार्थियों एवं पेशेवरों को आधुनिक पुनर्वास (रीहैबिलिटेशन) तकनीकों से संबंधित उन्नत व्यावहारिक ज्ञान एवं कौशल प्रदान करना था। कार्यशाला के मुख्य अतिथि एवं विशेषज्ञ वक्ता डॉ. मंजुल नौटियाल रहे। 24 जुलाई को आयोजित उद्घाटन समारोह में संस्थान के चेयरमैन डॉ. पंकज मुटनेजा, सीईओ ब्रिगेडियर जे.आर. सेठी, वीएसएम (सेवानिवृत्त), प्रिंसिपल प्रेम फिजियोथेरेपी एंड रिहैबिलिटेशन कॉलेज डॉक्टर विमल त्यागी, डाक्टर नेहा , सीएओ श्री जोगिंदर सिंह पीआरओ श्री एन.एन. पाण्डेय सहित संस्थान के सभी संकाय सदस्य एवं विद्यार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि डॉ. मंजुल नौटियाल देहरादून के स्वागत से हुआ। इस अवसर पर संस्थान के अध्यक्ष डॉ. पंकज मुटनेजा ने उन्हें पुष्पगुच्छ भेंट कर सम्मानित किया।

अपने संबोधन में डॉ. पंकज मुटनेजा ने आधुनिक चिकित्सा विज्ञान में फिजियोथेरेपी की बढ़ती महत्ता पर प्रकाश डालते हुए कहा कि आज फिजियोथेरेपी आधुनिक चिकित्सा विज्ञान का एक सशक्त एवं अभिन्न स्तंभ बन चुकी है। उन्होंने कहा कि टेपिंग तकनीक एवं ड्राई नीडलिंग जैसी उन्नत तकनीकों का प्रशिक्षण विद्यार्थियों के ज्ञान एवं व्यावहारिक दक्षता को समृद्ध करेगा तथा वे इन साक्ष्य-आधारित तकनीकों को अपने उपचार का प्रभावी हिस्सा बनाकर रोगियों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान कर सकेंगे। दो दिवसीय कार्यशाला के दौरान प्रतिभागियों को टेपिंग तकनीकों एवं ड्राई नीडलिंग से संबंधित विस्तृत सैद्धांतिक ज्ञान के साथ-साथ गहन हैंड्स-ऑन प्रायोगिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया। प्रशिक्षण में इन तकनीकों के वैज्ञानिक आधार, नैदानिक उपयोग, संकेत , निषेध तथा उनके प्रभावी एवं सुरक्षित क्रियान्वयन पर विशेष बल दिया गया, जिससे प्रतिभागियों की चिकित्सकीय दक्षता में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। कार्यशाला में हरियाणा एवं दिल्ली के लग-भग 120 फिजीयोथेरेपिस्ट ने भाग लिया। कार्यशाला का समापन 25 जुलाई 2026 को आयोजित समापन समारोह के साथ हुआ।

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित 'माइ भारत क्विज' में 3000 छात्रों ने भाग लिया

» कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

- थानेसर ब्लॉक के 100 स्कूलों में सफलतापूर्वक आयोजित करवाई गई 'माइ भारत क्विज'
- सांसद नवीन जिन्दल के मार्गदर्शन और कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में 'माइ भारत क्विज' के लिए प्रारंभिक परीक्षा का हुआ आयोजन।

देशभक्ति की भावना को मजबूत करने और छात्रों में राष्ट्रीय चेतना को जागृत करने के उद्देश्य से, फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया और शिक्षा विभाग कुरुक्षेत्र द्वारा 'माइ भारत क्विज' के लिए प्रारंभिक परीक्षा थानेसर ब्लॉक में सफलतापूर्वक संपन्न कराई गई।

सांसद एवं फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष नवीन जिन्दल के मार्गदर्शन और 'कारगिल विजय दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित क्विज के लिए प्रारंभिक परीक्षा ने विद्यार्थियों के बीच उत्साह और जागरूकता का एक नया वातावरण तैयार किया।

फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया के इस प्रयास की सराहना करते हुए जिला शिक्षा अधिकारी विनोद कौशिक ने बताया कि फ्लैग फाउंडेशन ऑफ इंडिया की इस विशेष पहल के अंतर्गत कुरुक्षेत्र में ब्लॉक थानेसर के 100 स्कूलों में एक साथ 'माइ भारत क्विज' की प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई, जिसमें लगभग 3000 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। प्रतियोगिता के माध्यम से छात्रों को भारत के इतिहास, स्वतंत्रता संग्राम और राष्ट्रीय ध्वज संबंधित जानकारी से जोड़ने का प्रयास किया गया । प्रारंभिक परीक्षा में विद्यार्थियों को 30 बहुविकल्पीय प्रश्नों का एक सेट प्रदान किया गया, जिसके माध्यम से उनकी सामान्य ज्ञान, तार्किक क्षमता और देश के इतिहास और स्वतंत्रता संग्राम के प्रति समझ का मूल्यांकन किया गया। जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी इन्दु कौशिक ने बताया कि इस परीक्षा का संचालन पूरी पारदर्शिता और व्यवस्थित तरीके से किया गया, जिससे विद्यार्थियों को एक निष्पक्ष और प्रेरणादायक प्रतिस्पर्धात्मक वातावरण प्राप्त हो सके। इस अवसर पर सांसद नवीन जिन्दल के संसदीय कार्यालय प्रभारी धर्मवीर सिंह पूर्व आईएएस ने जानकारी देते हुए बताया कि यह क्विज केवल एक प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक अभियान है, जिसका उद्देश्य देश के युवाओं को उनकी जड़ों से जोड़ना और उन्हें एक जागरूक एवं जिम्मेदार नागरिक बनाना है।

आदेश मेडिकल कॉलेज में भविष्य के डॉक्टरों को दिया गया जीवनरक्षक सीपीआर का प्रशिक्षण

प्रमोद कौशिक/ कुरुक्षेत्र, यूटर्न/ 25 जुलाई । भारतीय बाल रोग अकादमी (आईएपी) के राष्ट्रीय आईएपी सीपीआर मास अवेयरनेस डे के उपलक्ष्य में आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल मोहड़ी के बाल रोग विभाग द्वारा बेसिक लाइफ सपोर्ट (बीएलएस) एवं कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन (सीपीआर) पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। जिसकी शुरूआत आदेश मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल के निदेशक डा. गुणतास सिंह गिल ने की। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम का उद्देश्य केवल एक चिकित्सा प्रक्रिया सिखाना नहीं बल्कि ऐसे चिकित्सतक तैयार करना है जो आपातकालीन परिस्थितियों में आत्मविश्वास के साथ प्रभावी ढंग से कार्य कर सकें। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से सीपीआर के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा भावी चिकित्सकों को आपातकालीन परिस्थितियों में जीवन बचाने के लिए प्रशिक्षित करना है। प्रिंसिपल डा. एन एस लांबा ने कहा कि हृदयाघात के बाद शुरूआती कुछ मिनट मरीज के जीवन के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। इसलिए प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का सीपीआर में निपुण होना आवश्यक है। इस प्रशिक्षण में एमबीबीएस के 110 विद्यार्थियों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। उद्घाटन सत्र और आईएपी की जागरूकता वीडियो दिखाने के बाद विद्यार्थियों को तीन घंटे का व्यावहारिक प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के दौरान उन्हें चार अलग-अलग स्किल स्टेशनों पर वयस्क, बच्चों एवं शिशुओं को सीपीआर देने की तकनीक तथा गले में बाहरी वस्तु फंसने (एफबीएओ) की स्थिति से निपटने का अभ्यास कराया गया। कार्यक्रम का समापन प्रतिभागियों के फीडबैक सत्र और शपथ ग्रहण के साथ हुआ। इस अवसर पर निदेशक डा. गुणतास सिंह गिल, प्रिंसिपल डा. एनइस लांबा, डा. जी.एस. धनजल, डा. बलजीत मैनी, डा. विवेक मित्तल, डा. विक्रांत प्रभाकर तथा डा. नीरू शर्मा मौजूद रहे।

राहुल गांधी व कांग्रेस की मुहिम रंग लाई, केंद्रीय शिक्षा मंत्री का इस्तीफा: मधुसूदन बावेजा

अश्विनी वालिया/कुरुक्षेत्र। किसान कांग्रेस के जिला अध्यक्ष एडवोकेट मधुसूदन बावेजा ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह कांग्रेस और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी द्वारा छात्रों के मुद्दों को लगातार उठाने का परिणाम है। उन्होंने दावा किया कि राहुल गांधी ने विद्यार्थियों के हितों के लिए लगातार संघर्ष किया और सरकार पर दबाव बनाया। बावेजा ने कहा कि कांग्रेस का देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा में ऐतिहासिक योगदान रहा है तथा पार्टी हमेशा जनता के अधिकारों की लड़ाई लड़ती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार विभिन्न मुद्दों पर जनता की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर सकी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल जनता से जुड़े मुद्दों को लेकर सरकार का लोकतांत्रिक तरीके से विरोध जारी रखेंगे। उनके अनुसार शिक्षा, युवाओं और किसानों से जुड़े मामलों में सरकार को जवाबदेह बनाया जाएगा। बावेजा ने कहा कि जनता परिवर्तन चाहती है और कांग्रेस भविष्य में भी जनहित के मुद्दों को प्रमुखता से उठाती रहेगी।

RNI NO. PUNBIL/2014/59416 UTURNTIME.COM

यूटर्न टाइम

THE GOOD, BAD AND UGLY OF INDIA

FOLLOW US ON @UTURNTIMENEWS

पेज 07

खेसारी पर फूटा मलाइका का गुस्सा

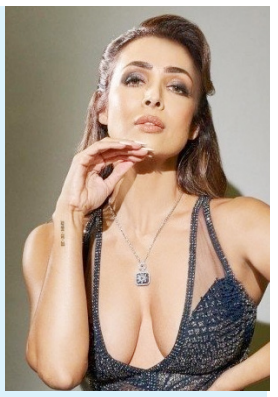

VOL: 03 | ISSUE 183 | SUNDAY DATE 26-07-2026 | RS 3 | PAGE-8 | PUBLISHED BY: DELHI | HINDI DAILY NEWSPAPER Visit at : www.uturntime.com

युवाओं के आगे झुकी सरकार : जेन Z की जंतर-मंतर पर जीत का ऐतिहासिक शंखनाद

धर्मेंद्र प्रधान ने मोदी को इस्तीफा सौंपा

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को शनिवार को अपना इस्तीफा सौंप दिया। छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी के विरोध-प्रदर्शन तथा विपक्ष द्वारा उनके इस्तीफे के लिए सरकार पर बनाये जा रहे दबाव के बीच श्री प्रधान ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर इसकी जानकारी दी। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा, 'पिछले 10 दिन का घटनाक्रम देखकर मेरा मन दुःखी है।

जंतर-मंतर पर और देश में जो स्थिति बनी है, इस स्थिति का राष्ट्र विरोधी ताकतें लाभ ना उठाएं, देश की एकता बनी रहे, देश के एक भी विद्यार्थी का भविष्य कानूनी पेचीदगियों में ना उलझे, हमारे बच्चे अपना समय पढ़ाई में लगाएं, करियर बनाने पर फोकस करें, इसी बात पर विचार करते हुए मैंने अपना त्यागपत्र प्रधानमंत्री जी को भेज दिया है।'

उन्होंने कहा कि देश की युवाशक्ति ही, इसकी असली ताकत है। देश की युवाशक्ति को भ्रम के कुचक्र में फंसने नहीं देंगे। केंद्रीय मंत्री ने कहा, 'यह मेरे लिए व्यक्तिगत प्रतिष्ठा का विषय नहीं है।' श्री प्रधान ने कहा कि गत 03 मई को हुई नीट परीक्षा में जो अनियमितताएं पाई गयी हैं उनसे उन्होंने कभी मुंह नहीं मोड़ा है और पहले दिन से ही जिम्मेदारी ली है।

राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकताः धर्मेंद्र प्रधान

जंतर-मंतर पर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के विरोध प्रदर्शन के बीच आखिरकार केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा पीएम मोदी को भेज दिया है। प्रधान ने कहा कि राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए धर्मेंद्र प्रधान ने लिखा कि मेरे युवा साथियों, मैं पिछले 4 दशकों से अधिक समय से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहा हूं। मेरा सदैव यह विश्वास रहा है कि एक सशक्त, समावेशी और दूरदर्शी शिक्षा व्यवस्था ही सशक्त राष्ट्र की आधारशिला होती है। मैं देश के युवाओं की आकांक्षाओं, भावनाओं और उनकी न्यायोचित अपेक्षाओं का गहरा सम्मान करता हूं। उन्होंने लिखा कि भारत की युवा पीढ़ी के सपनों को साकार करना हम सभी के राजनीतिक एवं सामाजिक जीवन का नैतिक संकल्प रहा है।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर सोनम वांगचुक बोले
'यह लोकतंत्र की जीत, अब जवाबदेही के बाद सुधारों की बारी'

केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद सोनम वांगचुक ने इसे लोकतंत्र की जीत करार दिया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि यह जीत सीधे सड़कों से निकले लोकतांत्रिक आंदोलन, शांति, धैर्य और निरंतर संघर्ष की जीत है। वांगचुक ने अपनी पोस्ट में लिखा, 'यह लोकतंत्र की जीत है... सीधे सड़कों से निकले प्रत्यक्ष लोकतंत्र की जीत। यह शांति, धैर्य और दृढ़ता की जीत है। कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी), देश की जेन जी जेनरेशन और उन सभी नागरिकों को बधाई, जिन्होंने डर और डर के माहौल से ऊपर उठकर देश के हर कोने से अपनी आवाज बुलंद की।' उन्होंने आगे लिखा, 'अब जवाबदेही के बाद सुधारों की बारी है।' वांगचुक की यह टिप्पणी ऐसे समय आई है जब नीट परीक्षा में कथित अनियमितताओं को लेकर लंबे समय से देशभर में विरोध प्रदर्शन चल रहे थे और जंतर-मंतर पर भी कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के नेतृत्व में आंदोलन जारी था। इससे पहले केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अपना इस्तीफा सौंपते हुए कहा कि 'राष्ट्रसेवा मेरे जीवन की सर्वोच्च प्राथमिकता है।' उन्होंने एक्स पर जारी लंबे संदेश में कहा कि वे पिछले चार दशकों से छात्र, शिक्षक और शिक्षा सुधार के लिए समर्पित रहे हैं तथा युवाओं की आकांक्षाओं और न्यायोचित अपेक्षाओं का हमेशा सम्मान करते रहे हैं।

अभिजीत दीपके बोले: 'झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए

मंच से अपने संबोधन में अभिजीत दीपके ने कहा कि यह जीत केवल किसी एक संगठन की नहीं, बल्कि उन लाखों छात्रों, अभिभावकों और नागरिकों की है जिन्होंने न्याय और जवाबदेही की मांग को मजबूती से उठाया। उन्होंने कहा, 'लोग कहते थे कि इस सरकार में इस्तीफे नहीं होते, लेकिन हमने करके दिखाया कि झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए।'

ह्ययह इस्तीफा नहीं, इंकलाब हैह्न, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी (सपा) के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि यह इस्तीफा नहीं इंकलाब है। सपा सांसद डिपंल यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से युवाओं को संबोधित किया। उन्होंने लिखा कि प्यारे बच्चों, यह जीत आपकी है। हम आपके साहस, दृढ़ संकल्प और लगन को सलाम करते हैं, जिसकी वजह से शिक्षा मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा। साथ ही, मुझे इस बात का बहुत अफसोस है कि आपको इतनी तकलीफ, मारपीट, सदमे और अपमान का सामना करना पड़ा। देश को बदलाव की जरूरत है। ऐसा बदलाव, जिससे सिस्टम में जान-बूझकर फैलाए गए भ्रष्टाचार को खत्म किया जा सके, ताकि देश तरक्की कर सके और हमारे देश के युवाओं की उम्मीदें और सपने पूरे हो सकें। ढेर सारा प्यार।

धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर गरजे राहुल गांधी, बोले-इस सरकार को हटाने का वक्त आ गया

लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को शिक्षा व्यवस्था को संवारने की दिशा में अहम कदम बताया है। राहुल गांधी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया, 'धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा शिक्षा व्यवस्था को फिर से संवारने की दिशा में बहुत बड़ा कदम है। शाबाश देशभर के छात्रों, आप सभी पर गर्व है। सड़कों पर आकर लोकतंत्र, संविधान और अपने भविष्य की रक्षा में डटकर खड़े होने वाले हर एक युवा, हर छात्र को बहुत-बहुत बधाई। उन्होंने पोस्ट में कुछ मांगों का जिक्र किया। राहुल गांधी ने लिखा कि 2 मांगें अभी बाकी हैं। प्रधानमंत्री छात्रों और भारत के भविष्य को सम्मान देते हुए माफी मांगें और छात्रों पर हिंसा के दोषियों पर कार्रवाई हो। समाज के दूसरे वर्गों किसानों, मजदूरों, गरीबों, हर वो व्यक्ति जिसे इस सरकार ने दबाया है, कुचला है-अपने सम्मान के लिए संवैधानिक तरीके से डटकर खड़े होने में ही असली साहस है।

सीजेपी का आंदोलन समाप्त होने के बाद सभी मेट्रो स्टेशन खुले

नीट पेपर लीक मामले को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के देश भर में जारी आंदोलन तत्काल प्रभाव से वापस लेने के बाद दिल्ली मेट्रो ने बंद किये गये सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार शनिवार शाम खोल दिये। सीजेपी से संसद मार्च के दिन से ही सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए मेट्रो ने जंतर-मंतर और संसद के आसपास के कई मेट्रो स्टेशन बंद कर दिये थे। आज भी सुबह 7.30 बजे से 18 मेट्रो स्टेशनों को बंद किया गया था। इनमें लोक कल्याण मार्ग, राजीव चौक, पटेल चौक, रामकृष्ण आश्रम मार्ग, बाराखंभा रोड, सुप्रीम कोर्ट, सेवा तीर्थ, जनपथ, मंडी हाउस, केंद्रीय सचिवालय, आईटीओ, दिल्ली गेट, इंद्रप्रस्थ, खान मार्केट, जोर बाग, शिवाजी स्टेडियम, झंडेवालान और नयी दिल्ली स्टेशन शामिल हैं। दिल्ली मेट्रो ने शाम 6.20 बजे के आसपास बताया कि दिल्ली मेट्रो नेटवर्क पर सभी मेट्रो स्टेशनों के प्रवेश द्वार खोल दिये गये हैं।

सरकार से अपनी मांगों पर आश्वासन मिलने के बाद सीजेपी ने वापस लिया आंदोलन

» नयी दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

पेपर लीक के मुद्दे पर पिछले एक महीने से अधिक समय से आंदोलन चला रही कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की घोषणा और सरकार की ओर से अपनी प्रमुख मांगों को मान लिये जाने के बाद शनिवार शाम को अपना आंदोलन वापस ले लिया।

राजधानी में आज केंद्रीय मंत्री जे.पी. नड्डा और जितेंद्र सिंह के साथ सीजेपी के प्रतिनिधियों सौरव दास और आशुतोष रांका के बीच चली लंबी बातचीत के बाद दोनों ओर से एक संयुक्त संवाददाता सम्मेलन में मांगों पर सहमति की घोषणा की गयी।

इसी मंच से सीजेपी के दोनों प्रतिनिधियों ने तत्काल प्रभाव से आंदोलन वापस लेने की घोषणा की। श्री सौरव दास ने कहा, 'श्री धर्मेंद्र प्रधान जी ने इस्तीफा दे दिया है। इसलिए हमारी पहली मांग पूरी हो गयी है।' उन्होंने कहा कि सरकार दिल्ली और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) तथा राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) शासित राज्यों में इस मुद्दे पर आंदोलन चला रहे विद्यार्थियों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियां वापस लेने की मांग भी मान ली है और भविष्य में भी इस प्रदर्शन को लेकर कोई कार्रवाई नहीं करने का आश्वासन दिया है।

सरकार ने इस मामले पर मंगलवार तक लिखित गारंटी देने का वादा किया है।

नीट पेपर लीक के बाद आत्महत्या करने वाले विद्यार्थियों के परिजनों को एक करोड़ रुपये के मुआवजे के मांग के संबंध में श्री नड्डा ने कहा, 'सरकार और प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी युवाओं के प्रति सहानुभूति रखते हैं। जिन बच्चों की मृत्यु हुई है, उनके परिजनों को नियम के अनुसार अधिकतम मुआवजा दिया जाएगा। श्री नड्डा ने कहा कि सीजेपी ने शिक्षा-परीक्षा में सुधार के संबंध में मांगों का जो चार्टर दिया है, उप पर सरकार विचार करेगी।

नीट पेपर लीक और छात्र आंदोलन के असली मुद्दे पर राजनीति हावी न हो : मायावती

» लखनऊ, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

बहुजन समाज पार्टी (बसपा) प्रमुख मायावती ने नीट-यूजी समेत विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक और उससे उपजे छात्र आंदोलन को लेकर कहा है कि इस मुद्दे पर सरकार और विपक्ष के बीच तेज राजनीतिक टकराव के कारण शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का वास्तविक मुद्दा कहीं दब न जाए।

उन्होंने पेपर लीक मामलों में जवाबदेही तय करने, दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की आवश्यकता पर जोर दिया। बसपा मुखिया मायावती ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर कहा कि देश में नीट-यूजी सहित विभिन्न परीक्षाओं के पेपर लीक व उसके उपरान्त परीक्षार्थियों द्वारा होने वाली आत्महत्याओं से उपजे छात्र-छात्राओं/युवाओं के ह्लकॉकरोच जनता पार्टीह्व (सीजेपी) आन्दोलन के नई दिल्ली जन्तर-मन्तर में लगातार जारी शांतिपूर्ण धरना को हालांकि लोगों की व्यापक सहानुभूति हासिल है, किन्तु सरकारी जवाबदेही के रूप में केंद्रीय शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की उनकी ज़िद्दी मांग को लेकर विपक्ष व सरकार दोनों के बीच जबरदस्त राजनीति का बाजार काफी गर्म है, जिससे शिक्षा व्यवस्था में जरूरी व्यापक सुधार का असली मुद्दा ही कहीं लुप्त ना हो जाये?

कैसे Gen Z ने बीजेपी के आईटी सेल को मात दी

संदीप शर्मा

करीब बारह सालों तक, BJP के IT सेल को भारत की सबसे मजबूत पॉलिटिकल कम्युनिकेशन मशीन माना जाता था। यह टीवी डिबेट शुरू होने से पहले ही एजेंडा तय कर देता था, ऐसे हैशटैग बनाता था जो सोशल मीडिया पर छा जाते थे, कुछ ही मिनटों में हजारों वॉलंटियर्स को इकट्ठा कर लेता था और अक्सर राजनीतिक विरोधियों को बैकफुट पर धकेल देता था। यह सिर्फ.एक कैंपेन टूल नहीं था; यह एक ऐसी संस्था बन गई थी जो राजनीतिक नैरेटिव को आकार देती थी। फिर आया **Gen Z** महंगे वॉर रूम के जरिए नहीं। संगठित पदानुक्रम **(hierarchies)** के जरिए नहीं। पार्टी के आधिकारिक ढांचे के जरिए नहीं। बल्कि मीम्स, व्यंग्य, मजाक और ऐसे इंटरनेट कल्चर के जरिए जो सिर्फ.इसलिए किसी अथॉरिटी का सम्मान करने से इनकार करता है क्योंकि अथॉरिटी इसकी मांग करती है। और जंतर-मंतर पर Gen Z, BJP के IT सेल से मीलों आगे था। BJP का डिजिटल दबदबा उस दौर के लिए बना था जब जानकारी एक सीधी लाइन में चलती थी—नेताओं से समर्थकों तक और फिर जनता तक। आज का इंटरनेट अलग तरह से काम करता है। यह विकेंद्रीकृत (decentralised) है, अव्यवस्थित है और इसे कंट्रोल करना नामुमकिन है। सबसे असरदार कंटेंट बनाने वाले अक्सर अनजान टीनएजर्स होते हैं जिनके पास स्मार्टफोन होता है, न कि पार्टी के पदाधिकारी जिनके पास स्प्रेडशीट होती है। BJP ने मैसेजिंग की राजनीति में महारत हासिल की। Gen Z ने रीमिक्सिंग की राजनीति में महारत हासिल की। हर सोच-समझकर बनाए गए राजनीतिक नारे के कुछ ही मिनटों में मीम बन जाने का खतरा रहता है। हर आधिकारिक कैंपेन वीडियो को ओरिजिनल वीडियो के व्यूज बढ़ने के दौरान ही क्लिप, एडिट और व्यंग्य में बदला जा सकता है। Instagram Reels, YouTube Shorts और वायरल कल्चर में पली-बढ़ी पीढ़ी राजनीति को भी वैसे ही देखती है जैसे मनोरंजन को—तेजी से, बिना किसी सम्मान के और आधिकारिक नैरेटिव के लिए ज्यादा सब्र रखे बिना। यह एक बड़ा बदलाव है। BJP का IT सेल तब बहुत अच्छा काम करता था जब Facebook, Twitter और WhatsApp अनुशासन और मैसेज को बार-बार दोहराने को बढ़ावा देते थे। नई पीढ़ी ऐसे प्लेटफॉर्म्स पर रहती है जो एल्गोरिदम से चलते हैं और जो संगठनात्मक ताकत के बजाय ओरिजिनैलिटी, मजाक और असलियत को बढ़ावा देते हैं। आज वायरल कंटेंट शायद ही कभी राजनीतिक मुख्यालय से निकलता है। यह अनगिनत स्वतंत्र क्रिएटर्स से निकलता है जो किसी के प्रति जवाबदेह नहीं होते। और वे Instagram पर बहुत ज्यादा निर्भर रहते हैं। मजाक एक पॉलिटिकल इक्वलाइजर (political equaliser) बन गया है। तथ्यों के उलट, मजाक का जवाब देना मुश्किल होता है। सरकारें आरोपों का खंडन कर सकती हैं, आंकड़ों को चुनौती दे सकती हैं या स्पष्टीकरण जारी कर सकती हैं। उन्हें मजाक का जवाब देने में मुश्किल होती है। एक बार जब कोई मीम लोगों की सोच पर छा जाता है, तो फैक्ट-चेक अक्सर बहुत देर से आते हैं। इंटरनेट यह बात लंबे समय से समझता है कि हंसी, लंबी आलोचना की तुलना में अथॉरिटी को ज्यादा असरदार तरीके से कमजोर कर सकती है। Gen Z स्वाभाविक रूप से इस भाषा को समझते हैं। वे वैचारिक बहस के बजाय व्यंग्य का इस्तेमाल करते हैं। भाषणों के बजाय, वे 15-सेकंड के वीडियो बनाते हैं। सोच-समझकर लिखी गई आलोचनाओं के बजाय, वे ऐसे विजुअल मजाक बनाते हैं जिन्हें किसी स्पष्टीकरण की जरूरत नहीं होती। उनका कंटेंट इसलिए शेयर नहीं किया जाता कि लोग राजनीतिक रूप से सहमत हैं, बल्कि इसलिए कि उन्हें यह मजेदार लगता है। यह एक ऐसा रणक्षेत्र है जहाँ संस्थागत अनुभव का बहुत कम फायदा मिलता है। रफ़्तार भी मायने रखती है। कभी IT सेल की तारीफ इसलिए होती थी कि वह कुछ ही घंटों में जवाब दे देता था। अब इंटरनेट कल्चर मिनटों में बदल जाता है। जो ट्रेंड सुबह छाया रहता है, वह शाम तक गायब हो सकता है। राजनीतिक संगठन, जो मंजूरी और मैसेजिंग के नियमों से बंधे होते हैं, हमेशा उन डिसेंट्रलाइज्ड क्रिएटर्स की तेजी का मुकाबला नहीं कर पाते जो तुरंत कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। हालाँकि, शायद सबसे बड़ी चुनौती तकनीकी नहीं, बल्कि सांस्कृतिक है। इस विरोध-प्रदर्शन ने सरकार को पहली बार मुश्किल स्थिति में डाल दिया है और उसे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे। सोनम वांगचुक ने अनशन तो तोड़ दिया है, लेकिन विरोध जारी है।

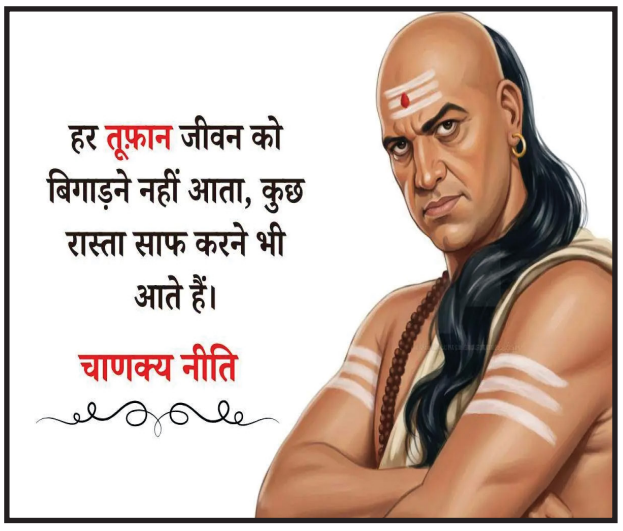

पेट्रोल में विरोध का विषय बना एथेनॉल अब रसोई तक पहुंचने की तैयारी में

एलपीजी का विकल्प बनने की दिशा में बड़ा कदम, ऊर्जा सुरक्षा, किसानों की आय और स्वच्छ ईंधन के नए युग की शुरूआत

कांतिलाल मांडोत

पेट्रोलियम मंत्रालय एथेनॉल को खाना पकाने के ईंधन के रूप में अपनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस नीति को सितंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें एथेनॉल आधारित चूल्हों के परीक्षण, उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। यदि यह योजना सफल होती है तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा।

भारत में एथेनॉल को लेकर पिछले कुछ वर्षों में सबसे अधिक चर्चा पेट्रोल में इसकी मिलावट (ब्लेंडिंग) को लेकर हुई। सोशल मीडिया से लेकर राजनीतिक मंचों तक कई तरह के दावे किए गए कि एथेनॉल वाहनों के इंजन को नुकसान पहुंचाएगा, माइलेज कम करेगा और इससे उपभोक्ताओं को नुकसान होगा। हालांकि समय के साथ वैज्ञानिक परीक्षणों, वाहन निर्माताओं के अनुभव और सरकार की नीतियों ने यह स्पष्ट किया कि निर्धारित मानकों के अनुरूप एथेनॉल मिश्रित ईंधन का उपयोग सुरक्षित है। अब यही एथेनॉल एक और बड़ी भूमिका निभाने की ओर बढ़ रहा है। केंद्र सरकार इसे घरेलू रसोई में एलपीजी के विकल्प के रूप में विकसित करने की तैयारी कर रही है। यदि प्रस्तावित नीति लागू होती है तो आने वाले वर्षों में भारत की रसोई में भी एथेनॉल आधारित चूल्हे दिखाई दे सकते हैं।

पेट्रोलियम मंत्रालय एथेनॉल को खाना पकाने के ईंधन के रूप में अपनाने के लिए एक व्यापक नीतिगत ढांचा तैयार कर रहा है। बताया जा रहा है कि इस नीति को सितंबर तक अंतिम रूप दिया जा सकता है। इसमें एथेनॉल आधारित चूल्हों के परीक्षण, उपभोक्ताओं को सब्सिडी देने, आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने और तेल विपणन कंपनियों के माध्यम से इसकी उपलब्धता सुनिश्चित करने जैसे महत्वपूर्ण प्रावधान शामिल किए जा सकते हैं। यदि यह योजना सफल होती है तो भारत ऊर्जा क्षेत्र में एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा।

एथेनॉल मूल रूप से कृषि उत्पादों से बनने वाला जैव ईंधन है। इसे गन्ने के रस, शीरे, मक्का और अन्य कृषि आधारित कच्चे माल से तैयार किया जाता है। यही कारण है कि इसे जीवाश्म ईंधनों की तुलना में अधिक पर्यावरण अनुकूल माना जाता है। अब तक इसका सबसे बड़ा उपयोग पेट्रोल में मिश्रण के रूप में किया जा रहा था, लेकिन नई सोच इसे सीधे घरेलू ईंधन के रूप में स्थापित करने की है।

सरकार का मानना है कि भारत हर वर्ष एलपीजी और अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के आयात पर भारी विदेशी मुद्रा खर्च करता है। यदि घरेलू स्तर पर तैयार होने वाला एथेनॉल खाना पकाने के ईंधन के रूप में लोकप्रिय होता है तो आयातित एलपीजी पर निर्भरता कम होगी। इससे विदेशी मुद्रा की बचत होगी और देश की ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी। आत्मनिर्भर भारत की दिशा में भी यह एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है।

इस योजना का सबसे बड़ा लाभ किसानों को भी मिल सकता है। एथेनॉल उत्पादन बढ़ने से गन्ना, मक्का और अन्य कृषि उत्पादों की मांग बढ़ेगी। इससे किसानों को बेहतर बाजार मिलेगा और कृषि आधारित उद्योगों का विस्तार होगा। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने एथेनॉल उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए अनेक डिस्टिलरी स्थापित करने को प्रोत्साहन दिया है। अब यदि घरेलू रसोई में भी इसकी मांग बढ़ती है तो किसानों की आय बढ़ाने का एक नया रास्ता खुल सकता है।

सूत्रों के अनुसार सरकार के आग्रह पर एथेनॉल आधारित कुकिंग स्टोव का परीक्षण किया जा रहा है। इन चूल्हों को इस प्रकार विकसित किया जा रहा है कि वे सुरक्षित, उपयोग में आसान और ऊर्जा दक्ष हों। परीक्षण सफल होने के बाद सरकार इनके लिए सब्सिडी या एकमुश्त वित्तीय सहायता की घोषणा कर सकती है ताकि आम परिवार भी इन्हें आसानी से अपना सकें। ठीक उसी प्रकार जैसे उज्ज्वला योजना के माध्यम से एलपीजी कनेक्शन का विस्तार किया गया था, भविष्य में एथेनॉल आधारित चूल्हों को भी प्रोत्साहित किया जा सकता है।

योजना का एक महत्वपूर्ण पहलू इसकी आपूर्ति व्यवस्था है। बताया जा रहा है कि पेट्रोल पंपों पर एथेनॉल उपलब्ध कराने के लिए विशेष एथेनॉल एटीएम विकसित किए जा सकते हैं। उपभोक्ता वहां से आवश्यक मात्रा में एथेनॉल खरीद सकेंगे और अपने कुकिंग स्टोव में उसका उपयोग कर सकेंगे। इससे वितरण व्यवस्था मजबूत होगी और अलग से नई आपूर्ति प्रणाली विकसित करने की आवश्यकता भी कम पड़ेगी।

जल संकट का असंतुलित प्रबंधनः अस्तित्व पर मंडराता खतरा

ललित गर्ग

जल केवल प्रकृति का उपहार नहीं, बल्कि मानव सभ्यता के अस्तित्व का आधार है। पृथ्वी पर जीवन की कल्पना जल के बिना असंभव है, फिर भी विडंबना यह है कि जिस जल को हमारी संस्कृति ने देवत्व प्रदान किया, उसी जल के प्रति हमारा व्यवहार सबसे अधिक लापरवाह रहा है। आज देश और दुनिया की सबसे गंभीर चुनौतियों में जल संकट प्रमुख बन चुका है। बढ़ती आबादी, अनियोजित शहरीकरण, अंधाधुंध भूजल दोहन, जलवायु परिवर्तन और वर्षाजल के समुचित प्रबंधन के अभाव ने इस संकट को भयावह बना दिया है। यदि समय रहते चेतना नहीं जागी तो आने वाले वर्षों में पानी केवल प्राकृतिक संसाधन नहीं, बल्कि सामाजिक तनाव, आर्थिक अस्थिरता और मानवीय संघर्ष का सबसे बड़ा कारण बन सकता है। हाल के शोध इस संकट की गंभीरता को और स्पष्ट करते हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) गांधीनगर के अध्ययन के अनुसार पिछले दो दशकों में उत्तर भारत का भूजल भंडार लगभग 450 घन किलोमीटर घट चुका है। यह मात्रा देश के सबसे बड़े जलाशयों में से एक इंदिरा सागर बांध की कुल जल संग्रहण क्षमता से लगभग 37 गुना अधिक है। यह आंकड़ा केवल वैज्ञानिक तथ्य नहीं, बल्कि भविष्य के संकट का स्पष्ट संकेत है। इसका अर्थ है कि जिस भूजल पर करोड़ों किसानों की खेती और करोड़ों लोगों का जीवन निर्भर है, वह तेजी से समाप्त हो रहा है।

इस भयावह स्थिति के पीछे सबसे बड़ा कारण जलवायु परिवर्तन है। वर्ष 1951 से 2021 के बीच

मानसूनी वर्षा में लगभग 8.5 प्रतिशत की कमी दर्ज की गई है। दूसरी ओर, उत्तर भारत में सर्दियों का तापमान भी बढ़ा है। तापमान में यह मामूली प्रतीत होने वाली वृद्धि भी मिट्टी की नमी को तेजी से कम करती है। परिणामस्वरूप खेतों को पहले की अपेक्षा अधिक सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। जब वर्षा कम होती है और सिंचाई की मांग बढ़ती है, तब किसान भूजल पर अधिक निर्भर हो जाते हैं। यही कारण है कि भूजल का पुनर्भरण कम और दोहन अधिक हो रहा है। आज भारत के अनेक क्षेत्रों में भूजल का स्तर हर वर्ष नीचे जा रहा है। पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, राजस्थान, दिल्ली और मध्य भारत के कई हिस्से इस संकट की चपेट में हैं। अनेक स्थानों पर सैकड़ों फीट गहराई तक बोरवेल खोदने के बाद भी पर्याप्त पानी नहीं मिल रहा। कई गांवों में हैंडपंप सूख चुके हैं और शहरों में टैंकर संस्कृति तेजी से बढ़ रही है। यह स्थिति बताती है कि यदि हमने अपनी जल नीति नहीं बदली तो आने वाले समय में पानी का संकट भोजन के संकट में भी बदल सकता है। भारत की कृषि व्यवस्था आज भी लगभग 80 प्रतिशत मीठे जल का उपयोग करती है। दुर्भाग्य से धान, गन्ना जैसी अधिक पानी वाली फसलें उन क्षेत्रों में भी उगाई जा रही हैं जहां जल संसाधन सीमित हैं। मुफ्त बिजली और सस्ते पानी की नीतियों ने कई क्षेत्रों में अनियंत्रित भूजल दोहन को बढ़ावा दिया है। जल का मूल्य शून्य समझे जाने के कारण उसका संरक्षण भी नहीं हो पा रहा। आवश्यकता इस बात की है कि कृषि नीति को जल उपलब्धता के अनुरूप बनाया जाए। जिन क्षेत्रों में पानी कम है, वहां मोटे अनाज, दालें, तिलहन तथा कम पानी में तैयार होने वाली फसलों को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। जल संकट केवल खेती तक सीमित नहीं है। उद्योगों, महानगरों और बढ़ते शहरी विस्तार ने भी भूजल पर अत्यधिक दबाव डाला है। बड़े-बड़े भवनों, कॉलोनियों और औद्योगिक क्षेत्रों में वर्षाजल सीधे नालों में बह जाता है। यदि प्रत्येक भवन में वर्षा जल संचयन की व्यवस्था अनिवार्य रूप से लागू हो जाए तो लाखों लीटर पानी हर वर्ष धरती के भीतर पहुंच सकता है। दुर्भाग्यवश अनेक राज्यों में कानून तो बने, लेकिन उनका प्रभावी पालन नहीं हो पाया।

जल संकट का एक और गंभीर पक्ष जल प्रदूषण है। देश की अधिकांश नदियां औद्योगिक अपशिष्ट, रासायनिक कचरे और सीवेज के कारण प्रदूषित हो चुकी हैं। जब नदियों और तालाबों का जल उपयोग योग्य नहीं रहता तो भूजल पर दबाव और बढ़ जाता है। इसलिए जल संरक्षण के साथ-साथ जल स्रोतों की स्वच्छता भी समान रूप से आवश्यक है। नदी केवल जलधारा नहीं, बल्कि सम्पूर्ण पारिस्थितिकी की जीवनरेखा है।

69,725 करोड़ रुपए के पैकेज से मिलेगी देश के जहाज निर्माण उद्योग को मजबूती

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई

केंद्र सरकार ने देश के जहाज निर्माण (शिपबिल्डिंग) उद्योग को नई गति देने के लिए 69,725 करोड़ रुपए के व्यापक पैकेज को मंजूरी दी है। इस पैकेज का उद्देश्य घरेलू जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाना, समुद्री क्षेत्र के लिए दीर्घकालिक वित्तपोषण उपलब्ध कराना और कौशल विकास को बढ़ावा देना है।

लोकसभा में पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्री सबार्नंद सोनोवाल ने बताया कि इस पैकेज के तहत भारतीय शिपयार्ड की लागत को वैश्विक शिपयार्ड के मुकाबले प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए 24,736 करोड़ रुपए की शिपबिल्डिंग फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम को मंजूरी दी गई है।

पैकेज का एक प्रमुख हिस्सा 25,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड है, जिसके जरिए जहाज निर्माण और समुद्री क्षेत्र को दीर्घकालिक वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें 20,000 करोड़ रुपए का मैरीटाइम इन्वेस्टमेंट फंड और 5,000 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट इंसेंटिवाइजेशन फंड शामिल है।

सरकार ने 19,989 करोड़ रुपए की शिपबिल्डिंग डेवलपमेंट स्कीम (एसबीडीएस) को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत ग्रीनफील्ड क्लस्टर विकसित करने और मौजूदा इकाइयों के ब्राउनफील्ड विस्तार के माध्यम से देश की जहाज निर्माण क्षमता बढ़ाकर प्रतिवर्ष 45 लाख ग्रॉस टनेज करने का लक्ष्य रखा गया है।

पत्तन, पोत परिवहन एवं जलमार्ग मंत्रालय के अनुसार, ये लक्ष्य मैरीटाइम इंडिया विजन 2030 और मैरीटाइम अमृतकाल विजन 2047 के अनुरूप भारत को वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धी जहाज निर्माण केंद्र बनाने के उद्देश्य से तय किए गए हैं। सरकार ने जहाज निर्माण उद्योग को बढ़ावा देने के लिए कई नीतिगत सुधार भी किए हैं। इनमें बड़े जहाजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा देना और जहाजों की मांग को एकीकृत करने जैसी पहल शामिल हैं। सरकार ने 19 सितंबर 2025 को 10,000 ग्रॉस टनेज (जीटी) या उससे अधिक क्षमता वाले भारतीय ध्वज वाले वाणिज्यिक जहाजों को इन्फ्रास्ट्रक्चर का दर्जा दिया था। इसके अलावा, भारत में निर्मित 1,500 जीटी या उससे अधिक क्षमता वाले जहाजों को भी यह दर्जा प्रदान किया गया है। मांग को एकीकृत करने की रणनीति के तहत 400 से अधिक जहाजों के अधिग्रहण की योजना तैयार की गई है, जिससे भारतीय शिपयार्ड को लंबे समय तक ऑर्डर मिलने की स्पष्टता मिलेगी।

संक्षिप्त खबरें

जीपी पेट्रोलियम्स का मुनाफा पहली तिमाही में तीन गुना होकर 20.6 करोड़ पहुंचा

मुंबई, यूटर्न/ 25 जुलाई । लुब्रिकेंट बनाने वाली कंपनी जीपी पेट्रोलियम्स लिमिटेड (जीपीपीएल) का मुनाफा (पीएटी) चालू वित्त वर्ष 2026-27 की पहली तिमाही में तीन गुना से अधिक होकर 20.6 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 6.4 करोड़ रुपये का मुनाफा कमाया था। कंपनी ने बताया कि समीक्षाधीन तिमाही में उसकी परिचालन आय सालाना आधार पर 46 प्रतिशत बढ़कर 230.3 करोड़ रुपये हो गई, जो 2025-26 की समान तिमाही में 158.2 करोड़ रुपये थी। कंपनी ने बताया कि वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में उसकी कर पूर्व आय करीब तीन गुना होकर 29.2 करोड़ रुपये हो गई, जो वित्त वर्ष 2025-26 की समान तिमाही में 10 करोड़ रुपये थी।जीपी पेट्रोलियम्स के प्रवक्ता ने कहा कि बेहतर परिचालन मार्जिन, उत्पाद मिश्रण में सुधार और परिचालन दक्षता पर लगातार ध्यान देने के साथ ही कंपनी ने वित्त वर्ष 2026-27 में मजबूत शुरूआत की है।

कठुआ को मिलेगी मजबूत बिजली, ग्रिड उन्नयन को 15.22 करोड़ मंजूर

- क्षेत्र में मिलेगी विश्वसनीय और गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति

श्रीनगर, यूटर्न/ 25 जुलाई । जम्मू कश्मीर सरकार ने क्षेत्र में बिजली आपूर्ति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से कठुआ ग्रिड स्टेशन के उन्नयन के लिए 15.22 करोड़ रुपए की एक महत्वपूर्ण परियोजना को हरी झंडी दे दी है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला के नेतृत्व वाली सरकार के इस फैसले की जानकारी एक सरकारी प्रवक्ता ने दी, जिसमें बढ़ती बिजली मांग को पूरा करने पर जोर दिया गया है। प्रवक्ता के अनुसार इस परियोजना का मुख्य लक्ष्य कठुआ ग्रिड स्टेशन की क्षमता में वृद्धि करना और उससे संबंधित बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाना है। यह पहल विशेष रूप से क्षेत्र में लगातार बढ़ती बिजली की मांग को पूरा करने के लिए पारेषण नेटवर्क को मजबूत करेगी और उपभोक्ताओं के लिए अधिक सुदृढ़ एवं विश्वसनीय विद्युत अवसंरचना उपलब्ध कराएगी। अधिकारियों का मानना है कि इस उन्नयन से पारेषण प्रणाली की विश्वसनीयता और स्थिरता में उल्लेखनीय सुधार होगा। साथ ही, यह प्रणाली पर पड़ने वाले अधिक दबाव को कम करने में भी सहायक होगा। इसका सीधा लाभ कठुआ और आसपास के क्षेत्रों के हजारों उपभोक्ताओं को मिलेगा, जिनके लिए अब बेहतर गुणवत्ता और अधिक स्थिर बिजली आपूर्ति सुनिश्चित हो सकेगी।

भारत की पहली हाइड्रोजन ट्रेन ने तय किया 1,200 किलोमीटर का सफर; 3,200 लीटर डीजल की बचत

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई

भारत की पहली स्वदेशी हाइड्रोजन ट्रेन, जो 10-कोच मॉडल है और संचालन के दौरान केवल जलवाष्प उत्सर्जित करती है, ने सफलतापूर्वक 1,200 किलोमीटर से अधिक का सफर तय किया है। इस दौरान 3,200 लीटर से अधिक डीजल की बचत हुई। यह जानकारी रेलवे मंत्रालय ने शनिवार को जारी एक आधिकारिक बयान में दी।

रेलवे मंत्रालय के अनुसार, हाइड्रोजन ट्रेन में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बीच होने वाली रासायनिक प्रक्रिया से ट्रेन के भीतर ही बिजली पैदा होती है। इस प्रक्रिया में उप-उत्पाद के रूप में केवल जलवाष्प निकलती है। मंत्रालय ने बताया कि यह पूरी प्रक्रिया धुएं से मुक्त है और इसमें

टेलपाइप कार्बन उत्सर्जन शून्य होता है। यही वजह है कि इसे वर्तमान समय की सबसे स्वच्छ रेल प्रोपल्शन तकनीक माना जा रहा है।

इस ट्रेन में दो हाइड्रोजन ड्राइविंग पावर कार हैं, जो कुल 2,400 किलोवाट की शक्ति प्रदान करती हैं। इन्हें लिथियम आयरन फॉस्फेट बैटरियों और हाइड्रोजन सिलेंडरों का भी समर्थन प्राप्त है। ट्रेन के लिए ग्रीन हाइड्रोजन को 500 बार तक के दबाव पर संग्रहित किया गया है, जबकि 350 बार के दबाव पर इसकी आपूर्ति की जाती है। कुल मिलाकर इसमें लगभग 3,000 किलोग्राम हाइड्रोजन संग्रहित करने की क्षमता है।

रेलवे मंत्रालय ने बताया कि ट्रेन में कई स्वतंत्र सुरक्षा प्रणालियां लगाई गई हैं, जो गैस रिसाव, अत्यधिक गर्मी, आग और धुएं का तुरंत पता लगा सकती हैं। इनके साथ ऑटोमैटिक शट-ऑफ सिस्टम, लगातार वेंटिलेशन, अंतरराष्ट्रीय सुरक्षा मानकों का पालन और सभी आवश्यक तकनीकी परीक्षण भी सुनिश्चित किए गए हैं। बयान के अनुसार, जींद और सोनीपत के बीच सफल संचालन के बाद अब जल्द ही इस ट्रेन का दिल्ली रूट पर भी ट्रायल शुरू किया जाएगा। मंत्रालय ने कहा कि भारत की हाइड्रोजन फ्यूल सेल ट्रेन ने देश में स्वदेशी हाइड्रोजन रेल इकोसिस्टम की नींव रखी है और यह टिकाऊ, शून्य-उत्सर्जन रेल परिवहन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

श्रीराम फाइनेंस का मुनाफा पहली तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़ा

» मुंबई, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनी श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड का मुनाफा चालू वित्त वर्ष 2026-27 की अप्रैल-जून तिमाही में 60 प्रतिशत बढ़कर 3,453 करोड़ रुपये रहा। मुख्य रूप से आय में वृद्धि से लाभ बढ़ा है। श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के एक कार्यकारी अधिकारी ने कहा कि शुद्ध ब्याज आय 33.67 प्रतिशत बढ़कर 8,056 करोड़ रुपये होने और शुद्ध ब्याज मार्जिन के पिछले वित्त वर्ष की समान अवधि के 8.11 प्रतिशत से बढ़कर 9.04 प्रतिशत होने से मुनाफे में वृद्धि हुई। उन्होंने कहा कि जापान के एमयूएफजी द्वारा 4.4 अरब डॉलर में कंपनी में 20 प्रतिशत हिस्सेदारी खरीदने से भी शुद्ध ब्याज मार्जिन बढ़ाने में मदद मिली।

एक्सिस एमएफ के पूर्व डीलर वीरेश जोशी पर 7 साल का प्रतिबंध

» मुंबई, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (सेबी) ने फ्रंट-रनिंग ट्रेडिंग के गंभीर आरोपों पर ऐक्सिस म्युचुअल फंड के पूर्व चीफ डीलर वीरेश जोशी पर सात साल के लिए प्रतिभूति बाजार में पाबंदी लगा दी है। उन पर 3 करोड़ रुपए का भारी जुर्माना भी लगाया गया है। इस मामले में सेबी ने जोशी के 20 अन्य सहयोगियों को भी 3 से 7 साल के लिए प्रतिबंधित किया है, जिन पर 10 लाख रुपए से 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना लगाया गया है। नियामक ने इस अवैध गतिविधि के जरिये हुई अनुमानित 30.55 करोड़ रुपए की कमाई को पहले ही जब्त कर लिया है। सेबी के अंतिम आदेश के अनुसार, जोशी ने अपने पद

का दुरुपयोग करते हुए ऐक्सिस एमएफ के बड़े सौदों से जुड़ी गोपनीय जानकारी अपने बाहरी सहयोगियों को दी। इन लोगों ने दुबई से ओडीआईएन टर्मिनल और दूसरों के नाम पर खोले गए खातों का इस्तेमाल कर फ्रंट-रनिंग ट्रेड किए, जिससे बाजार में हेरफेर कर अवैध मुनाफा कमाया गया। इस गैर-कानूनी कमाई को ऑफशोर कंपनियों में जमा किया गया। जांच में मिले व्हाट्सएप चैट और जादूगर, एएसडीएफजी जैसे कोड नामों के इस्तेमाल से आरोपियों के बीच गहरे तालमेल का खुलासा हुआ। बाजार नियामक ने स्पष्ट किया है कि फ्रंट-रनिंग एक गंभीर धोखाधड़ी है, जो म्युचुअल फंडों के यूनिटधारकों के भरोसे और बाजार की अखंडता को कमजोर करती है। ऐसी गतिविधियों में निजी फायदे को प्राथमिकता दी जाती है, जबकि म्युचुअल फंडों का प्रबंधन निवेशकों के हित के लिए किया जाता है।

सेबी की यह कार्रवाई बाजार में धोखाधड़ी रोकने और निवेशकों के हितों की रक्षा के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को दर्शाती है।

8वें वेतन आयोग की बैठकें अगस्त में, कर्मचारियों को मिली राहत

महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त को आयोजित की जाएंगी

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

केंद्र सरकार के लाखों कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए 8वें वेतन आयोग को लेकर एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। आयोग ने दिल्ली में विभिन्न कर्मचारी संगठनों और पेंशनर्स यूनियनों के साथ आगामी बैठकों का विस्तृत कार्यक्रम जारी कर दिया है। ये महत्वपूर्ण बैठकें 7 अगस्त और 10 अगस्त, 2026 को आयोजित की जाएंगी, जिनमें केंद्रीय कर्मचारियों के वेतनमान, भत्तों और पेंशन से संबंधित विभिन्न सुझावों पर गहन चर्चा की जाएगी। इस घोषणा से देश के लगभग 1.19 करोड़ केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स को राहत मिली है, जो लंबे समय से

आयोग की सिफारिशों का इंतजार कर रहे हैं। आयोग ने उन सभी कर्मचारी और पेंशनर्स संगठनों को एक और अवसर प्रदान किया है, जिन्होंने पूर्व में अपना मेमोरेंडम जमा कर दिया था, लेकिन किसी कारणवश अभी तक आयोग के साथ उनकी बैठक नहीं हो पाई थी। ऐसे संगठन इन आगामी बैठकों में शामिल होने के लिए 31 जुलाई, 2026 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते समय उन्हें अपनी मेमो आईडी के साथ अपॉइंटमेंट की मांग करनी होगी।

आयोग ने स्पष्ट किया है कि तय समय सीमा के बाद प्राप्त होने वाले अनुरोधों पर सीमित विचार किया जाएगा, इसलिए सभी संगठनों को निर्धारित तिथि से पहले प्रक्रिया पूरी करने की सलाह दी गई है। 8वें वेतन आयोग का मुख्य उद्देश्य केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए मौजूदा वेतन, भत्तों और पेंशन व्यवस्था की व्यापक समीक्षा करना है।

बच्चों की दवा कंपनी रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित

नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई । भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (एफएसएसएआई) ने बच्चों के लिए आयुर्वेदिक दवाएं, हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रिशन उत्पाद बनाने वाली कंपनी रेहान हेल्थकेयर का लाइसेंस निलंबित कर दिया है। यह सख्त कार्रवाई कंपनी की विनिर्माण इकाई के विस्तृत निरीक्षण के बाद की गई, जहां खाद्य सुरक्षा नियमों के कई गंभीर उल्लंघन पाए गए। एफएसएसएआई ने तत्काल प्रभाव से उत्पादन रोकने और सभी कमियों को दूर करने का निर्देश दिया है, अन्यथा कड़ी कानूनी कार्रवाई की चेतावनी दी है। एफएसएसएआई के निरीक्षण दल ने रेहान हेल्थकेयर की फैक्ट्री में अत्यधिक अस्वच्छ और दूषित वातावरण पाया। पूरे परिसर में गंदगी, कीड़े-मकौड़ों का प्रकोप और साफ-सफाई के बुनियादी मानकों की घोर अनदेखी उजागर हुई। कंपनी को खाद्य सुरक्षा अनुपालन में केवल 12 प्रतिशत अंक मिले, जो स्थिति की गंभीरता को दर्शाता है। अधिकारियों ने विनिर्माण टैंकों के नीचे गंदगी की मोटी परतें और कच्चे माल के भंडारण क्षेत्रों में भी अत्यधिक अस्वच्छता पाई, जिससे उत्पादों में संक्रमण फैलने का गंभीर खतरा पैदा हो रहा था। निरीक्षण में अपर्याप्त भंडारण, सीमित कार्यस्थल, खराब वेंटिलेशन और प्रकाश व्यवस्था जैसी अन्य महत्वपूर्ण कमियां भी सामने आईं। फैक्ट्री में मकड़ी के जाले, फफूंदी, मक्खियां और खुले में पड़ा कचरा आम बात थी। नियामक ने इस स्थिति को विशेष रूप से खतरनाक माना, क्योंकि यह इकाई बच्चों द्वारा उपभोग किए जाने वाले हाई रिस्क हेल्थ सप्लीमेंट्स और न्यूट्रास्यूटिकल्स बनाती है।

जंतर-मंतर आंदोलन की जीत पर बोले बलराज सभ्रवाल: युवाओं को झुकाया नहीं जा सकता, संविधान और अहिंसा बनी सबसे बड़ी ताकत

हरियाणा, यूटर्न/ 25 जुलाई । जंतर-मंतर पर हुए युवा आंदोलन से जुड़े बलराज सभ्रवाल, जो 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई के दौरान स्वयं आंदोलन स्थल पर मौजूद थे, ने आंदोलन की सफलता को लोकतंत्र की ऐतिहासिक जीत बताया। उन्होंने कहा कि यह आंदोलन आने वाले वर्षों तक इसलिए याद रखा जाएगा क्योंकि बिना किसी बड़े नेतृत्व, बिना संसाधनों, बिना राजनीतिक संरक्षण और बिना किसी षड्यंत्र के देश के युवाओं ने पूरी तरह शांतिपूर्ण और अनुशासित तरीके से अपना संघर्ष जारी रखा। बलराज सभ्रवाल ने कहा कि 20 जुलाई का दिन आंदोलनकारियों के लिए एक काला अध्याय था। उनके अनुसार 18 जुलाई को सोनम वांगचुक को तड़के हिरासत में लिया गया और इसके बाद 20 जुलाई को प्रदर्शनकारियों पर व्यापक पुलिस कार्रवाई की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि इस दौरान छात्रों, युवाओं, महिलाओं और बुर्जुगों पर लाठीचार्ज किया गया तथा आंसू गैस, पानी की बौछार और अन्य बल प्रयोग के साधनों का इस्तेमाल किया गया। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि कुछ लोग बिना नेम प्लेट वाली वर्दी में मौजूद थे।

अवैध रूप से साइकोट्रोपिक दवाएं सप्लाई करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, पिता-पुत्र समेत 5 गिरफ्तार

» नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई

नॉर्थ-ईस्ट डिस्ट्रिक्ट पुलिस ने साइकोट्रोपिक दवाओं की अवैध खरीद, भंडारण और आपूर्ति में शामिल एक अंतर-राज्यीय नेटवर्क का पदार्फाश करके एक और बड़ी कामयाबी हासिल की है। आरोपियों के कब्जे से 19.70 लाख से ज्यादा ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम टैबलेट, कैप्सूल (470.686 किलोग्राम) और एक टाटा सफारी को बरामद किया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों शिवम गुप्ता और वीरपाल गुप्ता से लगातार पूछताछ के बाद उनके साथी नदीम (30 साल) की पहचान हुई। नदीम मोहम्मद नईम का बेटा है और राजीव नगर का रहने वाला है। दिल्ली के चांदनी चौक स्थित भागीरथ पैलेस से अपना काम चला रहा था। उसके पास से ट्रामाडोल के 24 कैप्सूल (5 ग्राम), ट्रामाडोल की 16 गोलियां (10 ग्राम) और अल्प्राजोलम की 30 गोलियां (3 ग्राम) बरामद की गईं। इसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के दौरान आरोपी नदीम ने अपने सप्लायर की पहचान बताई। इस जानकारी पर तुरंत कार्रवाई करते हुए एक खास पुलिस टीम ने उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में छापा मारा और सप्लायर नवनीत (35 साल) को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान आरोपी नवनीत ने बताया कि उत्तर प्रदेश के नोएडा में अंबेडकर सिटी के एक बंद गोदाम में साइकोट्रोपिक दवाएं रखी गई थीं। उसकी जानकारी पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उस जगह की तलाशी ली और भारी मात्रा में दवाओं वाले 29 कार्टन और 270 ट्रामाडोल कैप्सूल (लगभग 86 ग्राम) बरामद किए। गोदाम के किराएदार फरार पाए गए और उनके मोबाइल फोन बंद थे।

आगे की जांच में एक और आरोपी, आशीष का नाम सामने आया, जो कथित तौर पर उस गोदाम से ट्रामाडोल और अल्प्राजोलम ले रहा था। उसे आरोपी नवनीत की जानकारी पर पकड़ा गया। शुरूआती तकनीकी जांच से दोनों आरोपियों के बीच डिजिटल कनेक्शन का पता चला। पुलिस कस्टडी रिमांड के दौरान नवनीत ने बताया कि उसने आशीष सिन्हा से साइकोट्रोपिक दवाएं ली थीं। उसकी जानकारी, तकनीकी सबूतों और डिजिटल एनालिसिस के आधार पर आरोपी आशीष सिन्हा (46), निवासी गणेश टॉवर, कृष्णा गार्डन, गाजियाबाद को ढूंढा गया और गिरफ्तार किया गया। उसके पास से एक मारुति बलेनो कार भी बरामद की गई। जांच को आगे बढ़ाते हुए जुलाई को पुलिस टीम ने मुख्य वांछित आरोपी शिव नारायण झा (45) निवासी ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर-2 को सफलतापूर्वक गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान, शिव नारायण झा ने अपने साथी अमन शर्मा (34 साल) की भूमिका के बारे में बताया, जिसे बाद में गिरफ्तार कर लिया गया। जांच में यह भी पता चला कि शिव नारायण झा नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) द्वारा दर्ज केस में एक घोषित अपराधी भी है।

गुराना के स्कूलों ने रचा कीर्तिमान: 1650 पौधे लगाकर दिया हरियाली का संदेश, 'एक पेड़ माँ के नाम' का दिया संकल्प

हरियाणा, यूटर्न/ 25 जुलाई । पर्यावरण संरक्षण को लेकर गुराना गांव के दोनों सरकारी विद्यालयों ने मिसाल कायम की है। गवर्नमेंट मॉडल संस्कृति प्राइमरी स्कूल और GSSS गुराना में को संयुक्त 'पौधरोपण अभियान' का आयोजन किया गया।

कार्यक्रम में जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी हांसी विनोद कुमार व प्रिंसिपल भाटला सुरजीत ने बतौर अतिथि शिरकत की। इस अवसर पर ग्राम पंचायत गुराना के सरपंच रामअवतार, GSSS गुराना के प्राचार्य बलजीत सिंह तथा GMSPS गुराना के मुख्याध्यापक राजेंद्र कुमार भी उपस्थित रहे। सरपंच व

DEEO ने अपने कर कमलों द्वारा दोनों स्कूलों में त्रिवेणी लगाकर पर्यावरण को बचाने का संकल्प लिया। इस दौरान उन्होंने बच्चों को पेड़ों के महत्व के बारे में समझाया और 'एक पेड़ माँ के नाम' अभियान के तहत पौधे लगाने हेतु प्रेरित किया। जानकारी दी गई कि अब तक प्राइमरी स्कूल में 650 और GSSS में 1000 पौधे सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। सभी पौधों की देखभाल विद्यार्थियों और स्टॉफ द्वारा नियमित रूप से की जा रही है।

कार्यक्रम के अंत में सभी बच्चों को 1-1 पौधा देकर उसे लगाने और पालने के लिए प्रोत्साहित किया गया।

कार्यक्रम के दौरान सरपंच रामअवतार, रटउ सदस्यों व मुख्याध्यापक राजेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से DEEO के समक्ष प्राइमरी स्कूल में अध्यापकों की कमी का मुद्दा उठाया।

संक्षिप्त खबरें

कार से टक्कर मारकर मारपीट व अपहरण मामले में 2 अन्य आरोपी गिरफ्तार

गुरुग्राम, यूटर्न/ 25 जुलाई । सेक्टर-5 थाना इलाके में एक व्यक्ति को कार से टक्कर मारकर मारपीट व अपहरण मामले में दो अन्य आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों में अंबेडकर नगर कॉलोनी का रामकुमार उर्फ रामू और यूपी के चित्रकूट का सत्यम श्रीवास्तव शामिल है। आरोपियों को बृहस्पतिवार को अंबेडकर नगर कॉलोनी से काबू किया गया। पुलिस प्रवक्ता संदीप कुमार ने बताया कि इससे पहले एक आरोपी देवीलाल कॉलोनी के रहने वाले रोहित को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। आरोपियों के पास से वारदात में प्रयोग की गई पिस्टल बरामद की गई है। आरोपियों से टीम पूछताछ कर रही है। ये वारदात 17 जुलाई को शीतला कॉलोनी के पास हुई थी। कार से टक्कर मारकर उसमें सवार चार आरोपियों ने पीड़ित को रॉड व डंडों से पीटा व जबरन कार में डाल लिया था। आरोपियों ने मोबाइल व अन्य सामान छीना और नहर के पास इसे फेंक गए। आरोप है कि कार से फेंकने के दौरान आरोपियों ने हवाई फायर भी किया था। सेक्टर-5 थाना में दर्ज प्राथमिकी पर जांच करते हुए अपराध शाखा सेक्टर-39 की टीम ने मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से पूछताछ में पता चला कि इस मामले में आरोपी रोहित अग्रवाल व शिकायतकर्ता के बीच पुराने झगड़े को लेकर रंजिश थी। इसी के कारण आरोपियों ने मिलकर वारदात को अंजाम दिया था।

सरकारी स्कूलों में शिक्षकों को रोज पढ़ाने होंगे छह पीरियड

गुरुग्राम, यूटर्न/ 25 जुलाई । शिक्षा विभाग ने सरकारी और वरिष्ठ माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के रेशनलाइजेशन के नए नियम लागू कर दिए हैं। नए नियम के तहत अब शिक्षकों का कार्यभार, कक्षाओं के सेक्शन और स्कूलों में पदों का निर्धारण नए तरीके से किया जाएगा। नई व्यवस्था के अनुसार कक्षा 6वीं से 12वीं तक के 50 विद्यार्थियों पर पहला सेक्शन बनाया जाएगा। इसके बाद 40 अतिरिक्त विद्यार्थियों पर नया सेक्शन मंजूर होगा। इससे स्कूलों में सेक्शन बनाने की प्रक्रिया पहले से अधिक स्पष्ट होगी। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के कार्यभार को लेकर भी नए निर्देश जारी किए हैं। अब पीजीटी, टीजीटी, सीएंडवी, एलिमेंट्री स्कूल हेडमास्टर और डीपीई को प्रतिदिन छह पीरियड पढ़ाने होंगे यानी सप्ताह में 36 से 40 पीरियड लेने होंगे।

विधायक विनोद भयाना के प्रयासों से समाप्त हुआ सेक्टरवासियों का धरना

सरकार का उद्देश्य अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति तक सभी मूलभूत सुविधाएं पहुचाना - विधायक विनोद भयाना

» राजेश सलूजा

हरियाणा, यूटर्न/ 25 जुलाई । हांसी के हुड्डा सेक्टर में पेयजल समस्या को लेकर पिछले कुछ समय से चल रहा धरना शनिवार को विधायक विनोद भयाना के सक्रिय हस्तक्षेप और सकारात्मक पहल के बाद समाप्त हो गया। विधायक विनोद भयाना स्वयं धरना स्थल पर पहुंचे, जहां उन्होंने सेक्टरवासियों से सीधा संवाद कर उनकी समस्याओं को गंभीरता से सुना। इसके उपरांत प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारियों के साथ विस्तृत चर्चा कर पेयजल समस्या के स्थायी समाधान के लिए एक ठोस कार्ययोजना (रोडमैप) तैयार किया गया, जिसे मौके पर ही धरनारत लोगों के समक्ष प्रस्तुत किया गया। इस दौरान विधायक विनोद भयाना के साथ एसडीएम राजेश खोथ, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के कार्यकारी अभियंता तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण (एचएसवीपी) के अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने पेयजल आपूर्ति से संबंधित तकनीकी एवं प्रशासनिक पहलुओं पर विस्तार से चर्चा की और समस्या के स्थायी समाधान के लिए समयबद्ध कार्यवाही का भरोसा दिलाया।

बैठक में अधिकारियों ने सेक्टरवासियों को बताया कि तैयार किए गए रोडमैप के अनुसार चरणबद्ध ढंग से आवश्यक कार्य किए जाएंगे, ताकि क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति को सुचारु, पर्याप्त एवं स्थायी बनाया जा सके। संबंधित विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समयसीमा में सभी आवश्यक कार्य पूर्ण करेंगे। विधायक विनोद भयाना के प्रयासों, प्रशासन की सकारात्मक पहल और अधिकारियों द्वारा दिए गए आश्वासन से संतुष्ट होकर सेक्टरवासियों ने अपना धरना समाप्त करने की घोषणा की।

युवाओं के लोकतांत्रिक संघर्ष की ऐतिहासिक जीत, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा छात्र शक्ति के आगे सत्ता के झुकने का प्रमाण : डॉ. ओमवीर सिंह पंवार

» निर्मल सिंह विर्क

पानीपत, यूटर्न/ 25 जुलाई । समाजसेवी एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता डॉ. ओमवीर सिंह पंवार ने शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि यह इस्तीफा इस बात का स्पष्ट प्रमाण है कि युवाओं की आवाज को न तो दबाया जा सकता है और न ही अनदेखा किया जा सकता। लोकतंत्र में जनता ही सर्वोच्च होती है और जब युवा अपने अधिकारों, भविष्य और न्याय की लड़ाई के लिए एकजुट होकर संघर्ष करते हैं, तब सत्ता को भी उनके सामने झुकना पड़ता है। उन्होंने कहा कि यह केवल किसी एक मंत्री का इस्तीफा नहीं है, बल्कि देश के लाखों संघर्षरत छात्र-छात्राओं के साहस, धैर्य, लोकतांत्रिक संघर्ष और अटूट संकल्प की ऐतिहासिक जीत है। इस आंदोलन ने यह सिद्ध कर दिया है कि सत्य और न्याय की लड़ाई कभी व्यर्थ नहीं जाती तथा लोकतंत्र में जनता की आवाज अंततः विजयी होती है।

डॉ. पंवार ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी एवं लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्री राहुल गांधी जी ने लगातार छात्रों और युवाओं के अधिकारों की आवाज बुलंद की है। जब-जब युवाओं के भविष्य पर संकट आया, प्रतियोगी परीक्षाओं में अनियमितताओं के आरोप लगे या छात्रों के साथ अन्याय हुआ, तब कांग्रेस पार्टी उनके साथ मजबूती से खड़ी रही और संसद से लेकर सड़क तक उनकी लड़ाई लड़ी।

उन्होंने कहा कि आदरणीय राहुल गांधी जी का स्पष्ट मानना है कि देश का युवा केवल रोजगार नहीं, बल्कि पारदर्शी व्यवस्था, निष्पक्ष परीक्षाएँ, ईमानदार भर्ती प्रक्रिया और समान अवसर चाहता है। कांग्रेस पार्टी युवाओं के इसी अधिकार की लड़ाई पूरी प्रतिबद्धता के साथ लड़ रही है और आगे भी लड़ती रहेगी।

डॉ. पंवार ने आंदोलन में शामिल सभी छात्र-छात्राओं को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएँ देते हुए कहा कि यह आपकी जीत है, यह सत्य की जीत है, यह लोकतंत्र की जीत है और यह भारत के संविधान में निहित जनशक्ति की जीत है। आपका संघर्ष आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा बनेगा और यह संदेश देगा कि लोकतांत्रिक तरीके से लड़ी गई लड़ाई कभी पराजित नहीं होती। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी देश के युवाओं को विश्वास दिलाती है कि जब-जब उनके अधिकारों पर कुठाराघात होगा, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा अथवा शिक्षा एवं रोजगार के अवसरों पर अन्याय होगा, तब-तब आदरणीय श्री राहुल गांधी जी के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी पूरी मजबूती, निडरता और संकल्प के साथ उनके अधिकारों की लड़ाई सड़क से लेकर सदन तक लड़ती रहेगी।

गोलू गुप्ता का सफर मेरे करियर का सबसे खास अनुभवः श्वेता त्रिपाठी

लोकप्रिय वेब सीरीज मिजार्पुर अब ओटीटी प्लेटफॉर्म की सीमाओं से निकलकर बड़े पर्दे पर अपनी उपस्थिति दर्ज कराने जा रही है। अभिनेत्री श्वेता त्रिपाठी एक बार फिर अपने बहुचर्चित और सशक्त किरदार गोलू गुप्ता के रूप में दर्शकों के सामने होंगी। अभिनेत्री ने अपने किरदार की यात्रा, इस फ्रेंचाइजी से जुड़े अपने गहरे अनुभव और दर्शकों से मिले अपार प्यार को लेकर कई महत्वपूर्ण बातें साझा कीं। उन्होंने बताया कि गोलू का किरदार समय के साथ कितना बदल गया है और कैसे वह एक सीधी-सादी लड़की से एक मजबूत और जटिल महिला तक का सफर तय कर चुकी है, जो सही और गलत की अपनी शुरूआती समझ से आगे बढ़ते हुए ताकत, दर्द, बदले और महत्वाकांक्षा जैसी कई भावनाओं से गुजरती है। श्वेता त्रिपाठी ने भावुक होते हुए कहा, जब हमने करीब आठ साल पहले मिजार्पुर की शूटिंग शुरू की थी, तब हममें से किसी ने भी यह कल्पना नहीं की थी कि यह सफर इतना लंबा, इतना खास और इतना प्रभावशाली होगा।

मांबननेकेसुखदपलोंकाआनं

खेसारीपरफूटा मलाइकाकागुस्सा

बॉलीवुड एक्ट्रेस मलाइका अरोड़ा इन दिनों भोजपुरी इंडस्ट्री के मशहूर एक्टर खेसारी लाल यादव पर दिए अपने कड़े बयान को लेकर अचानक सुर्खियों में आ गई हैं. सोशल मीडिया पर खेसारी लाल का एक वीडियो वायरल होने के बाद मलाइका का गुस्सा फूट पड़ा और उन्होंने खुलेआम एक्टर के रवैये पर सवाल खड़े कर दिए. दरअसल, यह पूरा मामला एक रेड कार्पेट इवेंट के दौरान बेजुबान जानवर के साथ हुई बदसलूकी से जुड़ा है, जिस पर खेसारी की चुप्पी देख मलाइका खुद को रोक नहीं पाईं और उन्होंने सोशल मीडिया पर उन्हें जमकर खरी-खोटी सुना दी. अमेजन प्राइम वीडियो के शो ह्यबैटलग्राउंडह्ल के रेड कार्पेट का एक वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है.

इस वीडियो में खेसारी लाल यादव कैमरों के सामने पोज देने के लिए पहुंचे थे. इसी दौरान रेड कार्पेट पर एक आवारा कुत्ता आ गया, जिसे वहां मौजूद इवेंट स्टाफ ने बेहद बेरहमी से घसीटकर बाहर कर दिया. चौंकाने वाली बात यह रही कि यह सब खेसारी लाल की आंखों के ठीक सामने हुआ, लेकिन उन्होंने स्टाफ को रोकने के बजाय चुपचाप खड़े होकर पोज देने का इंतजार किया. इवेंट स्टाफ की इस हरकत और खेसारी लाल की चुप्पी पर मलाइका अरोड़ा का गुस्सा सातवें आसमान पर पहुंच गया. जानवरों से बेहद लगाव रखने वाली मलाइका ने इस वायरल वीडियो को अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर री-शेयर करते हुए भोजपुरी एक्टर पर सीधा निशाना साधा. वीडियो पोस्ट करते हुए मलाइका ने कैप्शन में लिखा, ह्यये लोग कैसे हैं?

और यह कौन व्यक्ति है जो खड़ा होकर पोज दे रहा है... घिनौना.ह्ल मलाइका सिर्फ स्टोरी शेयर करके ही शांत नहीं हुईं, बल्कि उन्होंने उस वायरल वीडियो के कमेंट सेक्शन में जाकर भी अपनी भड़ास निकाली. उन्होंने एक कमेंट में लिखा, ह्यबेतुका,ह्ल तो वहीं दूसरे कमेंट में खेसारी पर सवाल उठाते हुए लिखा, ह्ययह बेवकूफ कौन है??? क्या उसके लिए पोज देना इतना जरूरी है??ह्ल मलाइका के इन कमेंट्स के बाद सोशल मीडिया पर भी इस मुद्दे को लेकर बहस छिड़ गई है. आपको बता दें कि खेसारी लाल यादव हाल ही में फिटनेस रियलिटी सीरीज ह्यबैटलग्राउंड सीजन 2ह्ल में नजर आए थे. इस शो में उनके साथ फुकरा इंसान (अभिषेक मल्हान), प्रियंका चाहर चौधरी और राहुल चौधरी जैसे मशहूर चेहरे भी शामिल थे. यह शो खास तौर पर मोबाइल-फर्स्ट ऑडियंस को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है, जिसमें ताकत, स्टैमिना और कड़ी टक्कर देखने को मिलती है.

फोटो स्टोरी

न्यूयॉर्क में आयोजित अमेरिकी एथलेटिक्स चैंपियनशिप की 100 मीटर दौड़ जीतने के बाद जश्न मनाते धावक नोआ लाइल्स।

मेरी पत्नी को गालियां दी गईं, परिवार को घसीटना गलत : हेड

विराट कोहली विवाद पर ट्रेविस हेड ने तोड़ी चुप्पी

नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई। इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में भारतीय टीम के पूर्व कप्तान विराट कोहली के साथ मैदान पर हुए विवाद को लेकर ऑस्ट्रेलियाई ओपनर ट्रेविस हेड ने पहली बार चुप्पी तोड़ी है। हेड ने एक इंटरव्यू में खुलकर बताया कि मैदान पर विराट के साथ वास्तव में क्या हुआ था और उसके बाद किस तरह उनकी पत्नी जेसिका डेविस और परिवार को सोशल मीडिया पर घसीटा गया, जिससे उन्हें काफी दुख पहुंचा। उन्होंने विराट कोहली के साथ किसी भी तरह के व्यक्तिगत मतभेद होने से साफ इनकार किया, लेकिन इस बात पर अफसोस जताया कि क्रिकेट के मैदान की घटनाएं उनके परिवार तक पहुंच गईं, जिसे उन्होंने बिल्कुल अनुचित ठहराया। ट्रेविस हेड ने विराट के साथ हुई कथित हैंडशेक घटना को लेकर कहा कि हमारे बीच ऐसा कुछ भी सुलझाने जैसा नहीं है। यह बस वही है जो हैड्ल प्रतियोगिता कैसे चली या क्या हुआ इसमें कोई आश्चर्य नहीं है जैसा कि उम्मीद थी। हेड ने अपनी पत्नी जेसिका डेविस की भी जमकर तारीफ की, जिन्होंने भारतीय प्रशंसकों द्वारा सोशल मीडिया पर फैलाई गई नफरत और ट्रोलिंग को बहुत ही संयम और मजबूती से संभाला। कोड स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में उन्होंने अपने दुख को साझा करते हुए कहा, मुझे लगता है कि जेसिका और मेरे पास इन चीजों पर एक शानदार सोच है। यह वह दुनिया है जिसमें हम रहते हैं और मुझे लगता है कि वह इस तरह की चीजों को अच्छे से संभालती है, इसमें वह अद्भुत है।

वैभव सूर्यवंशी की बल्लेबाजी के साथ गेंदबाजी पर भी टीम मैनेजमेंट की नजरें

» **नई दिल्ली, यूटर्न/ 25 जुलाई।**

पंद्रह वर्षीय युवा बल्लेबाज वैभव सूर्यवंशी ने अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में अपनी तूफानी बल्लेबाजी से सनसनी मचा दी है। हाल ही में जिम्बाब्वे के खिलाफ खेले गए पहले टी20 मैच में उन्होंने मात्र 18 गेंदों पर धुआंधार अर्धशतक जड़कर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। जिसके बाद से भारतीय क्रिकेट में एक नई और रोमांचक उम्मीद जगी है। उनकी बल्लेबाजी में परिपक्वता और आक्रामकता का बेहतरीन मिश्रण देखने के बाद अब साथ-साथ में गेंदबाजी की क्षमता बढ़ाने की ओर ध्यान देने की बात चल पड़ी हैं।

वैभव की उम्र अभी काफी कम है और उनकी प्रतिभा को देखते हुए यह अनुमान लगाया जा रहा है कि वह भारत के लिए लंबे समय तक क्रिकेट खेल सकते हैं। उनकी विस्फोटक बल्लेबाजी क्षमता को देखते हुए, टीम प्रबंधन अब उनकी गेंदबाजी क्षमताओं पर भी काम करना चाहता है। यह रणनीति भारतीय टीम के भविष्य की योजनाओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसके तहत युवा खिलाड़ियों को न केवल एक विशिष्ट कौशल, बल्कि एक संपूर्ण हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में विकसित किया जा रहा है।

भारतीय टीम के गेंदबाजी कोच सुनील जोशी ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में वैभव की प्रतिभा की जमकर सराहना की। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि सबसे पहले, उसकी बल्लेबाजी पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए। वह शानदार रहा है और मुझे खुशी है कि उसने इतना अच्छा प्रदर्शन किया है। यह उसके लिए एक बेहतरीन अवसर है। जोशी ने वैभव के अंतरराष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन के साथ-साथ उनके पिछले प्रदर्शनों का भी जिक्र किया। उन्होंने बताया कि वैभव ने अंडर19 विश्व कप फाइनल में भी अच्छा खेल दिखाया था और जिम्बाब्वे के खिलाफ कल के मैच में भी उनका प्रदर्शन उत्कृष्ट रहा, जिससे उनकी क्षमता पर टीम का विश्वास और बढ़ गया है। सुनील जोशी ने यह भी स्पष्ट किया कि वैभव की गेंदबाजी को विकसित करना टीम की दीर्घकालिक योजना का हिस्सा है। उन्होंने बताया, वैभव अपनी बल्लेबाजी को लेकर बहुत सहज रहा है। जब भी हमें उसकी गेंदबाजी पर काम करने का समय मिलेगा, मैं सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में उसके साथ काम करूंगा। जोशी ने आगे कहा कि जैसे ही वे वैभव को अच्छी गेंदबाजी करते देखेंगे, वे निश्चित रूप से और तेजी से उस पर ध्यान केंद्रित करेंगे।

यह दर्शाता है कि टीम मैनेजमेंट वैभव को केवल एक विध्वंसक बल्लेबाज के रूप में नहीं, बल्कि एक बहुमूल्य हरफनमौला खिलाड़ी के रूप में देख रहा है, जो भविष्य में भारतीय टीम के लिए मैच विजेता साबित हो सकता है। वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा प्रतिभा का उदय भारतीय क्रिकेट के लिए शुभ संकेत है और उनकी बहुमुखी प्रतिभा उन्हें आने वाले समय में टीम का एक महत्वपूर्ण सदस्य बना सकती है।

यूटर्न टाइम
THE GOOD, BAD & UGLY OF INDIA

फटाफट खबरें

जापान को फिर से सैन्य ताकत बढ़ाने से रोकना चाहिए : वांग यी

बीजिंग, यूटर्न/ 25 जुलाई । चीन ने कहा है कि चीन-रूस को दूसरे विश्व युद्ध में मिली जीत के नतीजों की रक्षा करनी चाहिए और जापान को फिर से हथियार उठाने से रोकना चाहिए। चीनी विदेश मंत्रालय ने शनिवार को शीर्ष चीनी राजनयिक के हवाले से कहा, 'दोनों देशों को रणनीतिक तालमेल को मजबूत करना चाहिए, द्वितीय विश्व युद्ध में मिली जीत के परिणामों की रक्षा करनी चाहिए और किसी भी परिस्थिति में जापान फिर से हथियार उठाने की अनुमति नहीं देनी चाहिए।' चीन के विदेश मंत्री वांग यी ने अपने रूसी समकक्ष सर्जेई लावरोव से शुक्रवार को किर्गिस्तान में मुलाकात की। चीनी अधिकारियों ने बार-बार कहा है कि जापान हाल के दिनों में आक्रामक हथियारों की तैनाती और अपने क्षेत्र से बाहर आक्रामक मिसाइलें लॉन्च कर दोबारा अपनी सैन्य ताकत बढ़ाने की प्रक्रिया तेज कर रहा है।

स्पेसएक्स के मेगा रॉकेट स्टारशिप की 13वीं परीक्षण उड़ान सफल

वॉशिंगटन, यूटर्न/ 25 जुलाई । अमेरिकी अंतरिक्ष कंपनी स्पेसएक्स ने टेक्सास स्थित स्टारबेस से अपने मेगा रॉकेट स्टारशिप की 13वीं परीक्षण उड़ान सफलतापूर्वक पूरी कर ली है। लॉन्च के लाइव प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग) में यह जानकारी दी गयी है। स्टारशिप रॉकेट ने शुक्रवार को अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 22:51 बजे (भारतीय समय अनुसार शनिवार तड़के 4:21 बजे) उड़ान भरी। रॉकेट के ऊपरी हिस्से ने परीक्षण उड़ान के दौरान हिंद महासागर में नियंत्रित तरीके से नीचे उतरने और पानी में सुरक्षित उतरने की प्रक्रिया पूरी की। रॉकेट अंतरराष्ट्रीय समयानुसार 23:57 बजे (भारतीय समय अनुसार शनिवार तड़के 5:27 बजे) हिंद महासागर में उतरा। स्पेसएक्स के अनुसार, एक घंटे से कुछ ज्यादा समय तक चली इस उड़ान के दौरान 20 स्टारलिंक वी3 उपग्रहों का सफल उप-कक्षीय परीक्षण किया गया और अंतरिक्ष में रैप्टर इंजन को पुनः चालू करने में सफलता मिली। इससे पहले इस परीक्षण उड़ान को तीन बार टाला गया था। पहली उड़ान तकनीकी खराबी के कारण आखिरी मिनट में रद्द कर दी गयी थी।
इसके बाद टेक्सास में खराब मौसम के कारण इसे दो बार और टालना पड़ा था।

ट्रंप का दावा: चीन और रूस नहीं करेंगे ईरान की मदद

वाशिंगटन, यूटर्न/ 25 जुलाई । अमेरिका और ईरान के बीच बढ़ते सैन्य संघर्ष के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक महत्वपूर्ण बयान दिया है। उन्होंने भरोसा जताया है कि इस युद्ध में चीन और रूस ईरान की कोई सीधी मदद नहीं करेंगे। हालांकि, इसके साथ ही उन्होंने दोनों देशों को चेतावनी भी दी कि यदि वे इस संघर्ष में शामिल होते हैं, तो उन्हें इसके बेहद गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। पत्रकारों से बातचीत करते हुए राष्ट्रपति ट्रंप ने बताया कि हाल ही में बीजिंग में हुई बैठक के दौरान चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने उन्हें व्यक्तिगत रूप से आश्वस्त किया था कि चीन न तो सीधे और न ही अपनी किसी कंपनी के माध्यम से ईरान को हथियारों की आपूर्ति करेगा। इसके अतिरिक्त, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भी उन्हें आश्वासन दिया है कि रूस तेहरान को किसी भी प्रकार के सैन्य हथियार नहीं बेचेगा।

फ्रांस-स्पेन में जंगल की आग बेकाबू, लाखों बेघर

» पेरिस, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

फ्रांस और स्पेन में लगी जंगल की आग विकराल रूप ले चुकी है। फ्रांस के दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में स्थिति गंभीर होने के बाद प्रशासन ने शनिवार को बॉरदॉ शहर के आसपास के इलाकों से हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। वहीं, स्पेनिश पीएम पेड्रो सांचेज ने ह्यराष्ट्रीय वाइल्डफायर इमरजेंसीह्व घोषित करत दी है।

फ्रांस के ला नोवेल-अकितेन और गिरोंद क्षेत्र की स्थानीय प्रशासन प्रमुख सोफी ब्रोका ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जानकारी दी कि ले हायालन, आइजिन और मेरिग्नाक इलाकों को खाली कराया जा रहा है।

फ्रांसीसी प्रधानमंत्री सेबेस्टियन लेकोर्नू ने बताया कि बॉरदॉ के पास स्थित गिरोंद और लांद क्षेत्रों से अब तक 1.41 लाख से अधिक लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा जा चुका है। इन्हीं इलाकों में इस सप्ताह की शुरूआत में जंगल की आग भड़की थी। प्रधानमंत्री लेकोर्नू ने एक्स पर लिखा, ' देश में लगी ये आग अब तक के सबसे गंभीर स्तर पर पहुंच चुकी है। आग पर नियंत्रण पाने के लिए फ्रांसीसी सेना को भी अभियान में लगाया गया है। फ्रांस सरकार ने दक्षिण-पश्चिमी हिस्से में फैली आग से निपटने के लिए अतिरिक्त सैन्य बल तैनात किए हैं। साथ ही धुएं से बचाव के लिए गिरोंद क्षेत्र में लोगों और बचावकर्मियों के लिए 15 लाख मास्क भेजे गए हैं।' गिरोंद प्रशासन ने बॉरदॉ के पश्चिमी उपनगरों के कुछ हिस्सों को खाली कराने का आदेश दिया है। इनमें शहर का हवाई अड्डा क्षेत्र भी शामिल है। इसके अलावा शहर के पश्चिम में स्थित कई अन्य कस्बों और गांवों को भी खाली कराया जा रहा है। प्रधानमंत्री लेकोर्नू के अनुसार, अब तक 500 से अधिक सैन्यकर्मी अग्निशमन दलों की मदद के लिए तैनात किए जा चुके हैं और जरूरत के अनुसार और जवान भेजे जाएंगे।

उन्होंने कहा कि मास्क का वितरण जमीन पर काम कर रहे कर्मचारियों और धुएं के संपर्क में आने वाले लोगों की सुरक्षा के लिए किया जा रहा है। वहीं, स्पेन में भी मैड्रिड के आसपास जंगल की आग की स्थिति को गंभीर बताया गया है। स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने प्रभावित इलाकों का दौरा करते हुए कहा कि हालात अभी भी 'जटिल' बने हुए हैं।

सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद ट्रंप ने बदली रणनीति, बोले- टैरिफ से अमेरिका में आया 19.2 ट्रिलियन डॉलर का निवेश

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 25 जुलाई

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी सरकार के नए टैरिफ का बचाव करते हुए कहा कि वे कानूनी चुनौतियों का सामना कर लेंगे। इन ड्यूटीज से अमेरिका में ट्रिलियन डॉलर का निवेश आया है।

नागरिक परमाणु ऊर्जा को लेकर एक कार्यक्रम के बाद व्हाइट हाउस में हुए सवाल-जवाब सत्र में राष्ट्रपति ट्रंप ने सरकार के नए टैरिफ एक्शन के लीगल बेसिस पर चिंताओं को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि उनके व्यापार एजेंडा से बहुत ज्यादा आर्थिक फायदे हो रहे हैं। ये टैरिफ लंबे समय से लगे हुए हैं। इन्हें सालों से मंजूरी मिली हुई है, हजारों मामलों में इन्हें मंजूरी मिली है। यह पूछे जाने पर कि क्या नए घोषित टैरिफ और यूरोपीय संघ से जुड़ी नई ट्रेड जांच न्यायिक जांच में टिक पाएगी, ट्रंप ने माना कि सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले के बाद सरकार ने अपने कानूनी तरीके में बदलाव किया है।

सिंध के जल की ह्यचोरीह्व का आरोप पीपीपी ने पाकिस्तान में निकाली रैलियां

» इस्लामाबाद, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

पाकिस्तान के सिंध प्रांत में सत्तारूढ़ पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी (पीपीपी) ने सिंधु नदी के जल की कथित 'चोरी' के विरोध में पूरे प्रांत में रैलियां निकालीं। पार्टी ने चेतावनी दी कि यदि उसकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा।

सिंध पीपीपी के अध्यक्ष निसार खुहरो के नेतृत्व में आयोजित रैली में पार्टी नेताओं, कार्यकर्ताओं और बड़ी संख्या में महिलाओं ने हिस्सा लिया। प्रदर्शनकारियों ने हाथों में तख्तियां लेकर 'सिंध के पानी की चोरी बंद करो' जैसे नारे लगाए।

शुक्रवार को रैली को संबोधित करते हुए निसार खुहरो ने कहा कि यदि पानी के बंटवारे में सिंध के साथ कथित अन्याय जारी रहा तो पार्टी आंदोलन के तीसरे चरण की शुरूआत करेगी। इसके तहत सिंध के सभी संभागीय मुख्यालयों पर बड़े पैमाने पर रैलियां आयोजित की जाएंगी।

उन्होंने दावा किया कि सिंधु नदी के पानी में प्रांत के संवैधानिक हिस्से से वंचित किए जाने के विरोध में पीपीपी ने पूरे सिंध में 130 स्थानों पर प्रदर्शन किए।

खुहरो ने कहा, 'जल ही जीवन है। जल के बिना जीवन संभव नहीं है, और हम किसी को भी अपने लोगों का भविष्य छीनने नहीं देंगे।' उन्होंने संघीय सरकार और इंडस रिवर सिस्टम अथॉरिटी (आईआरएसए) पर 1991 के जल बंटवारा समझौते को निष्पक्ष तरीके से लागू नहीं करने का आरोप लगाया। उन्होंने आरोप लगाया कि सिंध को बार-बार उसके हिस्से का पानी नहीं दिया जा रहा, जबकि पाकिस्तान के ऊपरी प्रांतों को प्राथमिकता दी जा रही है। पीपीपी नेता ने यह भी आरोप लगाया कि सिंध के हिस्से का पानी चश्मा-झेलम लिंक नहर, तौंसा-पंजनद लिंक नहर और जलालपुर नहर के जरिए दूसरी ओर मोड़ा जा रहा है। उनका कहना था कि कानूनी और संवैधानिक आपत्तियों के बावजूद ऐसा किया जा रहा है। खुहरो के अनुसार, इन लिंक नहरों का उपयोग केवल बाढ़ की स्थिति में किया जाना था, लेकिन इन्हें नियमित रूप से संचालित किया जा रहा है, जिससे सिंध तक पहुंचने वाले पानी की मात्रा लगातार घट रही है। उन्होंने कहा कि पानी के इस मोड़ से सिंध की कृषि भूमि बंजर होती जा रही है..

एआई और रोबोटिक्स में चीन की बढ़त रोकने की तैयारी अमेरिकी सांसदों ने जताया जासूसी का खतरा

» वाशिंगटन, यूटर्न/ 25 जुलाई

अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेट सांसदों के एक समूह ने इस सप्ताह एक ऐसे विधेयक को आगे बढ़ाया, जिसका उद्देश्य चीन में निर्मित मानव जैसे और चार पैरों वाले रोबोट को अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे का हिस्सा बनने से रोकना है।

सीनेटरों ने चेतावनी दी कि बीजिंग उसी रणनीति का इस्तेमाल कर रहा है, जिसका सहारा लेकर उसने वैश्विक ड्रोन बाजार में अपना दबदबा बनाया था। उनका कहना है कि इंटरनेट से जुड़े ऐसे चीनी रोबोट का इस्तेमाल भविष्य में जासूसी और महत्वपूर्ण प्रणालियों को नुकसान पहुंचाने के लिए किया जा सकता है। अमेरिकी प्रतिनिधि सभा की एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी की कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी सब कमेटी में ह्यगार्ड एक्टह्व नाम के इस प्रस्तावित विधेयक पर सुनवाई हुई। इस दौरान संचार सुरक्षा, एआई, ब्रॉडबैंड विस्तार और अवैध रोबोकॉल से जुड़े कई विधेयकों पर भी चर्चा की गई। रिपब्लिकन और डेमोक्रेट, दोनों दलों के सांसदों ने तर्क दिया कि अमेरिका को तब तक इंतजार नहीं करना चाहिए, जब तक चीनी रोबोटिक्स तकनीक अमेरिकी उद्योगों में व्यापक रूप से इस्तेमाल होने न लगे। उनका कहना था कि इससे पहले ही कदम उठाना जरूरी है, ताकि चीन में निर्मित रोबोट अमेरिका के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में अपनी पकड़ न बना सकें। समिति के अध्यक्ष ब्रेट गुथरी ने कहा कि अमेरिकी कांग्रेस पहले ही चीन की कंपनियों द्वारा निर्मित दूरसंचार उपकरणों और चीन में बने ड्रोन के खिलाफ कार्रवाई कर चुकी है। उन्होंने कहा, 'हम चीन जैसे प्रतिद्वंद्वी देशों से पैदा होने वाले खतरों के प्रति लगातार सतर्क हैं और अमेरिका के महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की सुरक्षा तथा नागरिकों के डेटा की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हैं।' उन्होंने यह भी कहा कि हाल ही में सामने आई उन रिपोर्टों, जिनमें चीन से जुड़े एक कथित षड्यंत्र के तहत अमेरिका के संचार नेटवर्क को ठप करने की योजना का दावा किया गया था.

यूनेस्को ने वेस्ट बैंक और लेबनान के ऐतिहासिक स्थल विश्व धरोहर सूची में शामिल

इजरायल की आपत्ति दरकिनार

» सोल, यूटर्न/ 25 जुलाई ।

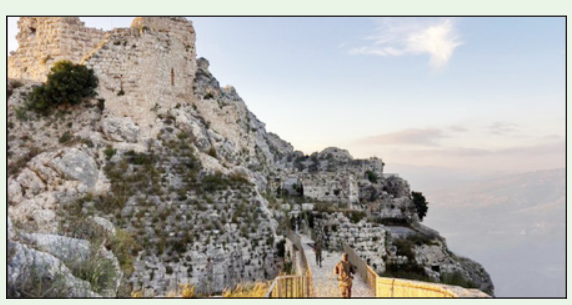

यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र की शिक्षा, विज्ञान और सांस्कृतिक संगठन) ने इजरायल की आपत्तियों को दरकिनार करते हुए वेस्ट बैंक के एक प्रमुख पुरातात्विक स्थल और दक्षिणी लेबनान के पांच ऐतिहासिक किलों को विश्व धरोहर सूची में शामिल कर लिया है। इनमें लेबनान का ब्यूफोर्ट कैसल (किला) भी है जिस पर हाल ही में इजरायल ने कब्जा किया था। क्रूसेडर काल का यह ऐतिहासिक किला कलाअत अल-शकीफ के नाम से भी जाना जाता है। इसे मई में लेबनान में हिजबुल्लाह के खिलाफ अभियान के दौरान इजरायली सेना ने अपने कब्जे में लिया था।

विश्व धरोहर सूची में डालने का निर्णय शुक्रवार को दक्षिण कोरिया के बुसान में आयोजित यूनेस्को की बैठक में लिया गया। इससे कुछ दिन पहले इजरायल के विदेश मंत्रालय ने समिति से इन प्रस्तावों को अस्वीकार करने की अपील की थी। हालांकि, समिति ने मध्य पूर्व में जारी संघर्षों का हवाला देते हुए आपातकालीन आधार पर नामांकनों की समीक्षा की और वेस्ट बैंक के सेबास्तिया नगर और लेबनान के माउंट अमेल क्षेत्र के पांच किलों को विश्व धरोहर सूची के साथ-साथ संकटग्रस्त विश्व धरोहर सूची में भी शामिल करने का फैसला किया। यूनेस्को के अनुसार, कब्जे वाले वेस्ट बैंक के नाबलुस के पास स्थित सेबास्तिया पुरातात्विक स्थल में विभिन्न सभ्यताओं के क्रमिक शासन और बसावट के प्रमाण सुरक्षित हैं, जिनका इतिहास ईसा पूर्व 9वीं शताब्दी तक जाता है। वहीं, लेबनान के माउंट अमेल क्षेत्र के ये पांच किले मध्यकाल से लेकर 19वीं शताब्दी के बीच के हैं। यूनेस्को ने कहा कि ये किले क्रूसेडर, अय्यूबी, ममलूक, उस्मानी (ऑटोमन) शासन तथा स्थानीय सामंती शासकों के अलग-अलग दौर और उनके अनुसार हुए निर्माण व बदलाव को दर्शाते हैं।

Owner, Publisher, Printer: - Komal Sharma, C/O Ummpl Marketing Pvt. 194-G, Sector 63, Noida 201307, Editor: Sandeep Sharma
Contact - +91 9888200619
* तमाम प्रकाशित सामग्री के चयन व संपादन हेतु आर.बी.एक्ट. के तहत जिम्मेवार *